

# वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004



भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय  
भारत सरकार



# भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

## विषय सूची

### भारी उद्योग विभाग

### लोक उद्यम विभाग

अध्याय	पृष्ठ सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय - प्रस्तावना	07	1. लोक उद्यम सर्वेक्षण	75
2. भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक	11	2. सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण	77
3. उल्लेखनीय उपलब्धियां	17	3. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	79
4. सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यम	20	4. मानव संसाधन विकास	83
5. भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र	33	5. सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	87
6. आटोमोटिव उद्योग	39	6. श्रमशक्ति योजितकीकरण एवं सुरक्षा तंत्र	89
7. प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	44	7. परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजना योजना	90
8. अल्पसंख्यकों का कल्याण	50	8. सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	91
9. सतर्कता	51	9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	92
10. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	52	10. महिलाओं का कल्याण	93
11. महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	54	अनुबंध (I से VI)	94
अनुबंध (I से X)	55		
संकेताक्षर	70		





## भारी उद्योग विभाग

● भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय - प्रस्तावना	07
● भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक	11
● उल्लेखनीय उपलब्धियां	17
● सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यम	20
● भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र	33
● आटोमोटिव उद्योग	39
● प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	44
● अल्पसंख्यकों का कल्याण	50
● सतर्कता	51
● हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	52
● महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	54
अनुबंध (I से X)	55
संकेताक्षर	70



## भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

### प्रस्तावना

#### मंत्रालय

1.1 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखने एवं उनके लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने के अलावा देश में पूंजीगत सामग्री एवं इंजीनियरी उद्योगों के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं।

#### भारी उद्योग विभाग

1.2 भारी उद्योग विभाग भारी इंजीनियरी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा 48 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रशासित करता है। इस विभाग द्वारा शामिल उद्योग इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, तेल शोधक कारखानों, पेट्रो-रसायन; नौवहन, कागज; सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के उपकरणों की आवश्यकता पूरी करते हैं। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर तथा गियर बॉक्स जैसे अनेक मध्यस्थ उत्पादों के विकास के लिए उत्तरदायी है। वे विद्युत, रेल और सड़क परिवहन आदि सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सामग्री और सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह विभाग पलक्कड़ में फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीच्यूट नामक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला भी प्रशासित करता है, जो चिन्हांकन के मानकीकरण के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

1.3 विभाग विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ नियमित तालमेल रखता है और उद्योग के विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है। यह विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार से संबंधित समस्याओं के समाधान, प्रौद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन तथा उन्नयन और अनुसंधान तथा विकास आदि के माध्यम से उद्योग की सहायता भी करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव है, जिसकी सहायता आर्थिक सलाहकार और एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-I** में दिया गया है।

1.5 यह विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ उनके कार्यनिष्पादन का अनुवीक्षण करने के लिए घनिष्ठ तालमेल रखता है। विभाग इन उद्यमों और सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है और ऑर्डर बुक सुधारने तथा मुख्य क्षेत्र के ग्राहकों को सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घावधिक संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है।

#### विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

1.6 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्रियों के विनिर्माण, परामर्श और संविदा कार्यकलापों में लगे हुए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में दिनांक 31 मार्च, 2004 की यथास्थिति कुल निवेश (सकल ब्लॉक) लगभग 8599 करोड़ रुपए था (**अनुबंध-II**) निवेश के संगणन में उन नौ सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो बंद हो गए हैं शामिल नहीं हैं। विभाग के अधीन उद्यम मशीन टूल; औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रोटेर्बाइन; टर्बो जेनरेटर; रेलवे ट्रैक्शन उपकरण, प्रेशर वेसल्स, एसी रेल इंजन, प्राइम मूवर्स, विद्युत उपकरण, और कृषि संबंधी ट्रैक्टर तथा घड़ियां, कागज, टायर और नमक जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह विभाग ऑटो क्षेत्र में एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड के कार्यों से भी संबंध रखता है।

1.7 यह विभाग सरकार की सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के अनुरूप और साथ ही कामगारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है तथा उसे प्रोत्साहित करता है। सरकारी क्षेत्र

के रुग्ण उद्यमों के संबंध में पुनरुद्धार पैकेज का निर्माण करने के लिए विभाग बी.आई.एफ.आर और अन्य संबंधित एजेंसियों से परस्पर संबंध बनाए रखता है।

- 1.8 यह विभाग वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है ताकि उनकी निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और सरकार/बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्गठन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रुग्ण/घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निधियां प्रदान की जा सकें। विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जनशक्ति यौक्तिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिनांक 31.3.2004 की यथास्थिति कर्मचारियों की कुल संख्या **अनुबंध-III** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 1,00,628 थी।

### नागरिक अधिकार पत्र

- 1.9 सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसलिए भारी उद्योग विभाग प्रभावी तथा प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव और निदेशक क्रमशः संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) की रूप में कार्यरत हैं।
- (ii) व्यावसायिक कार्यालय प्रबंध की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता सुधारने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज प्रारंभ करने और प्रणाली उन्नयन के लिए भी उत्तरदायी है।

(iii) पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए इस विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

(iv) कर्मचारियों की शिकायतों (लोक अदालत में विवाद) के निपटान के लिए इस विभाग में कार्यरित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

(v) अन्य महत्वपूर्ण सूचना के अतिरिक्त वर्ष 2003-2004 की अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वार्षिक रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(vi) विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के समाधान से संबंधित कार्य के लिए विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(vii) महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग में अवर सचिव स्तर की एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है।

### लोक उद्यम विभाग (लोउवि)

- 1.10 तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का सतत् मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। वर्तमानतः यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा अर्थव्यवस्था



में सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही यह विभाग कार्य-निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, वित्तीय लेखांकन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देशों का निर्धारण भी करता है। लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी उद्यमों के मध्य अन्तरापृष्ठ प्रदान करता है।

### लोक उद्यम विभाग के अधिदेश

1.11 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:-

- i) औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित लोक उद्यम ब्यूरो।
- ii) सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर-वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- iii) सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली से संबंधित मुद्दे।
- iv) सरकारी उपक्रमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मुद्दे।
- v) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

### लोक उद्यम विभाग की भूमिका

1.12 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंधन तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में नीति प्रतिपादित करने में सहायता प्रदान करता है। लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन

व अनुरक्षण भी करता है। अपने दायित्वों के निर्वहन में यह अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय भी करता है।

1.13 लोक उद्यम विभाग के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:-

- औद्योगिक प्रबंधन पूल, जिसे लोक उद्यम विभाग को अंतरित कर दिया गया है, से जुड़े मुद्दे सहित सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्य।
- संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक वार्षिक लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन।
- निदेशक मण्डल की संरचना, श्रेणीकरण, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कार्यपालकों का प्रशिक्षण।
- मिनीरत्न व नवरत्न श्रेणी के सरकारी उपक्रमों की समीक्षा।
- केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में आरक्षण से संबंधित मुद्दे।
- अन्तरराष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई), स्लोवेनिया से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को राष्ट्रपति के निर्देश तथा अन्य दिशानिर्देश जारी करना।
- केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डल को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।
- केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराना।
- क्रय अधिमानता से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के बीच तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों व केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के मध्य उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवादों (कराधान तथा रेलवे संबंधी मामलों को छोड़कर) के समाधान के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित मुद्दे।

— केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श व पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

### लोक उद्यम विभाग के प्रभाग

- (i) वित्तीय नीति प्रभाग में लोक उद्यम सर्वेक्षण एकक, नीति नियोजन एकक, मजूरी कक्ष तथा क्रय अधिमानता कक्ष शामिल हैं।
- (ii) प्रबंध नीति प्रभाग में कार्मिक नीति एकक, नवरत्न तथा मिनीरत्न एकक, प्रशिक्षण एकक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कक्ष शामिल हैं।
- (iii) समझौता ज्ञापन प्रभाग में समझौता ज्ञापन एकक, आंकड़ा बैंक तथा कम्प्यूटर कक्ष शामिल हैं।

(iv) प्रशासन तथा समन्वयन प्रभाग में प्रशासन, पुस्तकालय, संसद अनुभाग, समन्वय स्कंध तथा हिन्दी अनुभाग शामिल हैं।

(v) स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)।

(vi) परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन प्रभाग।

1.14 इस विभाग के अध्यक्ष सचिव हैं तथा उनकी सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव, दो निदेशक तथा 121 कर्मचारियों की समग्र संस्वीकृत संख्या वाला एक संगठन है।

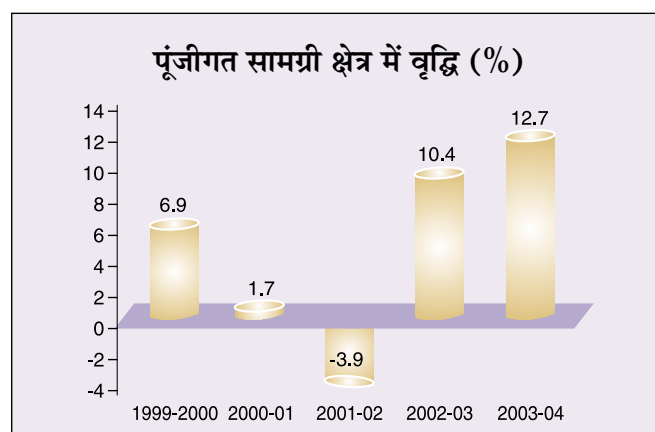
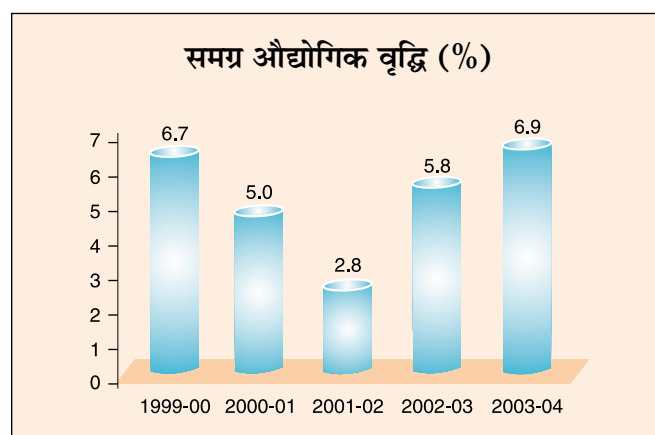
लोक उद्यम विभाग का संगठन-चित्र अनुबंध-1 में दिया गया है।

## भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यानिष्पादन की एक झलक

### 2.1 उद्योग का कार्यानिष्पादन

- वर्ष 2002-2003 के दौरान देखा गया औद्योगिक सुधार चालू वर्ष के दौरान भी जारी रहा जब अप्रैल-मार्च, 2003-2004 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 5.7 प्रतिशत की तुलना में समग्र औद्योगिक वृद्धि (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में मापित) 6.9 प्रतिशत की दर पर हुई।
- अप्रैल-मार्च, 2003-2004 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने यहां तक कि 7.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर दर्शाई है और इसके बाद क्रमशः खनन और उत्खनन तथा विद्युत क्षेत्र ने 5.1 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई है।
- प्रयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार पूंजीगत सामग्रियों ने अप्रैल-मार्च, 2003-2004 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 10.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- प्रयोग-आधारित वर्गीकरण से यह भी पता चलता है कि उपभोक्ता सामग्री क्षेत्र ने वर्ष 2002-2003 के समान वृद्धि दर (7.1%) बनाई रखी। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उप-क्षेत्र ने वर्ष 2002-2003 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि के बाद आमूल चूल परिवर्तन दर्शाया है। इसने अप्रैल-मार्च, 2002-2003 के दौरान 6.3 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत अप्रैल-मार्च, 2003-2004 के दौरान 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु उप-क्षेत्र ने अपनी वृद्धि की गति बनाई रखी है। इसने वर्ष 2003-2004 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

- बुनियादी और मध्यवर्ती सामग्री उद्योग ने अप्रैल-मार्च, 2003-2004 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 4.9 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- चालू वर्ष के दौरान ऑटो क्षेत्र ने असाधारण रूप से अच्छा कार्य किया है। वाणिज्यिक वाहन और यात्री कारों ने अप्रैल-मार्च, 2003-2004 में क्रमशः 38.4 प्रतिशत और 39.2 प्रतिशत की मात्रात्मक वृद्धि से उत्तम कार्यानिष्पादन दर्ज किया है।



- 2.2 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है:

- (i) बॉयलर
- (ii) सीमेंट मशीनरी उद्योग
- (iii) डेयरी मशीनरी उद्योग
- (iv) विद्युत भट्ठी
- (v) माल कन्टेनर
- (vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर उद्योग
- (vii) धातुकर्म मशीनरी
- (viii) खनन उद्योग
- (ix) मशीन टूल उद्योग
- (x) तेल क्षेत्र उपस्कर
- (xi) मुद्रण मशीनरी
- (xii) लुगदी और कागज मशीनरी
- (xiii) रबड़ मशीनरी उद्योग
- (xiv) स्विचगियर और कंट्रोलगियर
- (xv) शंटिंग लोकोमोटिव
- (xvi) चीनी मशीनरी उद्योग
- (xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
- (xviii) ट्रांसफॉर्मर
- (xix) वस्त्र मशीनरी उद्योग

2.3 अप्रैल-मार्च, 2003-2004 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्तियां नीचे सारणी में दी गई हैं:

क्षेत्रवार			
	भार	2002-03 (अप्रैल-मार्च)	2003-04 (अप्रैल-मार्च)
समग्र	1000.0	5.7	6.9
खनन और उत्खनन	104.7	5.8	5.1
विनिर्माण	793.6	6.0	7.2
विद्युत	101.7	3.2	5.0
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण			
समग्र	1000.0	5.7	6.9
बुनियादी सामग्रियां	355.6	4.9	5.4
पूंजीगत सामग्रियां	92.5	10.5	12.7
मध्यवर्ती सामग्रियां	265.1	3.9	6.2
उपभोक्ता सामग्रियां	286.6	7.1	7.1
(i) टिकाऊ वस्तुएं	53.6	-6.3	11.6
(ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएं	232.9	12.0	5.7

2.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ उद्योगों का अप्रैल-मार्च, 2003-2004 की अवधि के लिए उत्पादन और वृद्धि दर अप्रैल-मार्च, 2002-2003 की तुलना में नीचे दिया गया है:

	इकाई	उत्पादन अप्रैल-मार्च 2002-03	उत्पादन अप्रैल-मार्च 2003-04	वृद्धि दर (%)
औद्योगिक	लाख रुपए	आंकड़े		
मशीनरी	लाख रुपए	178715.58	208008.25	16.4
मशीन टूल	लाख रुपए	271939.82	221740.58	1.7
बॉयलर	लाख रुपए	218747.16	215791.80	-1.4
टर्बाइन (स्टीम/हाइड्रो)	लाख रुपए	65721.50	79322.21	20.7
विद्युत जेनरेटर	लाख रुपए	80790.17	114910.36	42.2
विद्युत और वितरण	मिलियन	74.45	60.94	-18.2
ट्रांसफॉर्मर	केवीए			
दूरसंचार केबल	मिलियन मीटर	20803.31	20373.71	-2.1
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	198827	275098	38.4
यात्री कार	संख्या	575426	801169	39.2

## 2.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन सकारी क्षेत्र के उद्यम

2.5.1 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदात्मक कार्यकलापों में लगे हैं। सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 9 सरकारी क्षेत्र के उद्यम बंद कर दिए गए हैं। अनन्तिम परिणामों (2003-2004) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों ने लाभ अर्जित किए हैं और शेष 30 ने घाटा उठाया है। 3 उद्यम अप्रचालनात्मक हैं। सरकारी क्षेत्र के शेष 36 उद्यमों का कुल कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ में)

	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (अनन्तिम)
उत्पादन	11470	12142
लाभ (+)/हानि (-)	(-844)	(-883)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम-बार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-IV और V में उपलब्ध हैं।

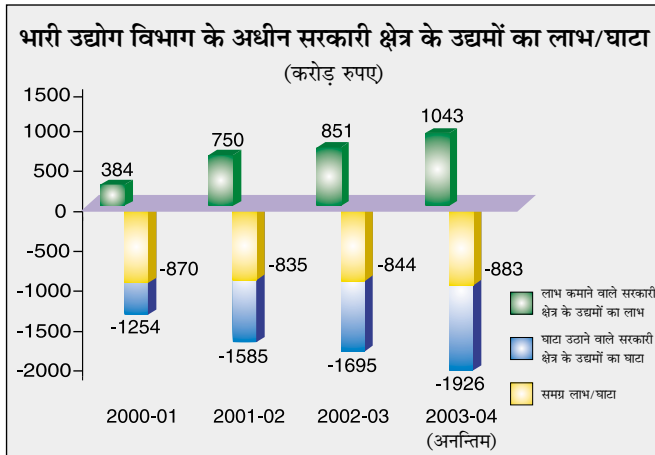
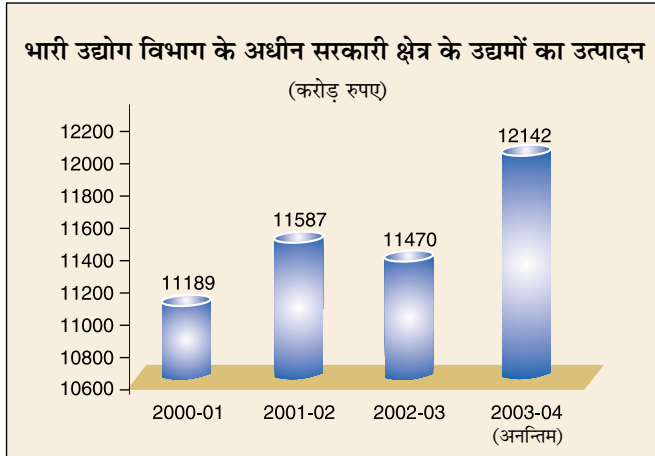
2.5.2 निविष्टियों की लागत में वृद्धि के अतिरिक्त मांग में गिरावट, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष जनशक्ति, पुराने संयंत्र और मशीनरी के कारण कुछ मुख्य उद्यमों में उत्पादन में कमी के कारण हानि हुई।

2.5.3 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उद्योग के मानदंडों से बहुत अधिक विशाल कार्यबल और भारी उपरिव्यय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय अनुबंध-VI में दिए गए हैं।

2.5.4 'भेल' के मामले, जहां ऑर्डर बुक होना 10,000-12,000 करोड़ रुपए के स्तर से काफी सुधरकर 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, को छोड़कर अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऑर्डर बुक होना धीरे-धीरे घट रहा है। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में ऑर्डर बुक होने का ब्यौरा अनुबंध-VII में दिया गया है।

2.5.5 ऐसी केवल कुछ ही कंपनियां हैं, जो अपने उत्पादों का निर्यात करने में समर्थ रही हैं। निर्यात करने वाले मुख्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम 'भेल' और एचएमटी हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निर्यात निष्पादन का ब्यौरा अनुबंध-VIII में दिया गया है।

2.5.6 इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकार का निवेश 3850 करोड़ रुपए है। कई सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपना निवल मूल्य पार करते हुए पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं। सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संग्रहित घाटा/लाभ अनुबंध-IX में दिया गया है।



## 2.6 भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन की कार्यनीतियां

2.6.1 पूर्वनीति के अनुसार, विभाग संभावित रूप से जैव्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार, उन सरकारी क्षेत्र को उद्यमों, जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है, को बंद करना, अगर आवश्यक हो सभी गैर-महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी को कम करके 26% अथवा इससे नीचे लाना और कामगारों के हितों के पूर्ण संरक्षण का ध्यान रख रहा है। इस प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई सूचीबद्ध है:

- बीआईएफआर के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार

- जहां भी उपयुक्त हो वित्तीय पुनर्गठन
- प्रौद्योगिकी, वित्त, विपणन, प्रबंधन आदि तक निरंतर पहुंच के लिए संयुक्त उद्यम का गठन
- जनशक्ति यौक्तिकीकरण

## 2.7 बीआईएफआर को संदर्भित सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.7.1 सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 19 उद्यम बीआईएफआर को संदर्भित किये गये हैं। बीआईएफआर को संदर्भित करने से पूर्व इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(i)	मामले, जहां बीआईएफआर ने पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत की है।	<b>8</b> i) भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड ii) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड iv) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड v) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड vi) नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड vii) रिचर्डसन एंड क्रूडस लिमिटेड viii) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
(ii)	मामले, जहां बीआईएफआर ने बंद करने की सिफारिश की है।	<b>3</b> i) भारत ऑर्थोलिम्क ग्लास लिमिटेड ii) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड iii) नगालैंड पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड
(iii)	बीआईएफआर की अंतिम सिफारिशे प्रतीक्षित हैं	<b>8</b> i) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ii) भारत वेगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड iv) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड v) हिंदुस्तान केबल लिमिटेड vi) नेपा लिमिटेड vii) प्रागा टूलस लिमिटेड viii) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

## 2.8 सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों का पुनर्गठन

2.8.1 बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने स्वयं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निम्नलिखित 7 मामले में पुनर्गठन योजनाएं अनुमोदित की हैं। इस पुनर्गठन योजनाओं में वित्तीय व्यावसायिक और संगठनात्मक पुनर्गठन शामिल हैं, जिसमें 531 करोड़ रुपए की नई राशि और 1443 करोड़ रुपए का वित्तीय पुनर्गठन शामिल है।

- एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाई एंड कंपनी)
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)
- हिंदुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल)
- एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी)

- (v) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)
- (vi) नेपा लिमिटेड (नेपा)
- (vii) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

## 2.9 संयुक्त उद्यम का गठन/विनिवेश

2.9.1 आरंभ किए जा चुके कुछ पुनर्गठन संबंधी पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 1999 में एंड्रयू यूल एंड कंपनी के बेल्डिंग प्रभाग का भागीदार की 74% इक्विटीधारिता और शेष 26% एवाई एंड कंपनी के पास रखते हुए जर्मनी की मैसर्स फिनीक्स के साथ संयुक्त उपक्रम (फिनीक्स यूल एंड कंपनी) में परिवर्तन।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एलजेएमसी) का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन और कंपनी प्रबंधन का जुलाई, 2000 में संयुक्त उद्यम भागीदार को हस्तान्तरण।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन और कंपनी के प्रबंधन का अगस्त, 2003 में संयुक्त उद्यम भागीदार को हस्तांतरण।

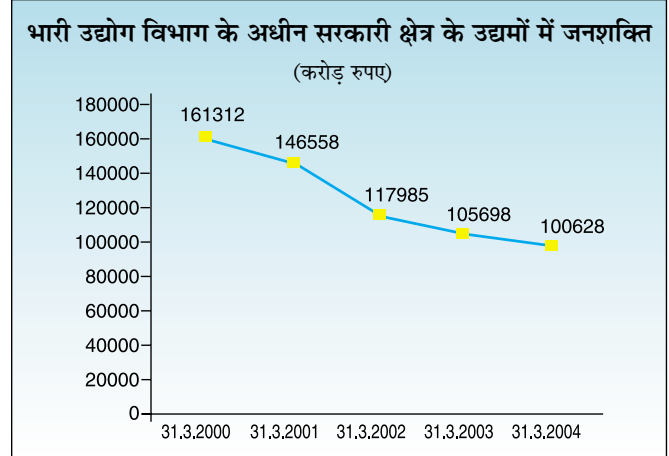
2.9.2 सरकारी क्षेत्र के 26 उद्यमों को विनिवेश/संयुक्त उद्यम गठन करने के लिए हाथ में लिया गया है जिसमें से 14 मामलों पर विनिवेश मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है और शेष 12 सरकारी क्षेत्र के उद्यम की सहायक कंपनी पर भारी उद्योग विभाग में कार्रवाई की जा रही है।

## 2.10 जनशक्ति का यौक्तिकीकरण

2.10.1 इस विभाग के कई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कामगारों को व्यर्थ कठिनाई दिए बिना अधिशेष जनशक्ति समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है। पिछले बारह वर्षों की अवधि 1992-1993 से 2003-2004 के दौरान लगभग 81,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया है, जिसमें लगभग 2400 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

2.10.2 यह विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए विदेशी निवेशकों/बैंको/संस्थानों/जनता को सरकारी गारंटी

के विरुद्ध बाण्ड जारी करने के लिए भी प्रोत्साहित करता रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा ब्याज संबंधी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।



## 2.11 सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/अजैव्य उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) लागू करना

2.11.1 जहां सरकार जैव्य और विश्वसनीय पुनरुद्धार योजनाओं का समर्थन करती रही है वहीं कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बीआईएफआर/विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा अजैव्य माना गया था और निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बंद कर दिया गया है:

- (i) भारत प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई)
- (ii) भारत ब्रेक्स एंड वाल्ब्स लिमिटेड (बीबीवीएल)
- (iii) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)
- (iv) नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)
- (v) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएएमसी)
- (vi) रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (आरआईसी)
- (vii) आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल)
- (viii) टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड (टेम्फो)
- (ix) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)

2.11.2 उपरोल्लिखित सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों के अतिरिक्त, एचएमटी लिमिटेड (वाच केस डिवीजन, लैम्प डिवीजन, सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट सभी हैदराबाद में और

गुवाहाटी में मिनिएचर बैटरी यूनिट), घाटा उठा रही रिफ़ैक्टरी यूनिट और बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) का जेलिंगम यार्ड, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की टांगरा यूनिट को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति के फलस्वरूप बंद कर दिया गया है।

## 2.12 सरकारी क्षेत्र से संबंधित सरकार की नई नीति

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत परिचालित नीति के अनुसार :-

- प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में प्रचालनरत सरकारी क्षेत्र के सफलतापूर्वक लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता दी जाएगी।
- सामान्यतः लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को निजीकरण नहीं किया जाएगा।
- प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर पारदर्शी और परामर्शदात्री तरीके से सभी निजीकरण पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आधुनिकीकरण और पुनर्गठित करने तथा रुग्ण उद्योग को पुरनरूद्धार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे जबकि सभी कामगारों को उचित देय राशि और क्षतिपूर्ति राशि मिल जाने के बाद चिरकाल से घाटा उठा रहे उद्यमों को या तो बेच दिया जाएगा या बन्द कर दिया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि निजीकरण की प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायता मिले।

2.12.1 इस नीति को ध्यान में रखकर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के भविष्य पर अन्तिम विचार करते समय प्रत्येक को अच्छी तरह से जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और सरकार से अपेक्षित सहायता अनुमान की जांच की जा रही है।

## 2.13 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

2.13.1 'भेल' नवरत्नों में से एक है। कंपनी के बोर्ड को योग्य व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव

संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने के संबंध में अधिक स्वतंत्रता दी गई है।

2.13.2 'भेल' को अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के तीन उद्यम यथा, आरईआईएल, एचएनएल और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न घोषित किया गया है।

## 2.14 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

2.14.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपने उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ ही अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2004-2005 के लिए भारत सरकार के साथ सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 5 उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
- (ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)
- (iii) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)
- (iv) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचपीसी की सहायक कंपनी)
- (v) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आईएलके की सहायक कंपनी)

## 2.15 पूर्वोत्तर क्षेत्र

2.15.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उद्यम/इकाइयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

- (i) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स), असम
- (ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड
- (iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम
- (iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

2.15.2 सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयों कागज, सीमेंट और चाय की विनिर्माण में लगी हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के

विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनाओं में हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई में ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरुद्धार शामिल है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के

लिए प्रदान की गई सरकार की बजटीय सहायता क्रमशः 7.12 करोड़ रुपए, 4.34 करोड़ रुपए और 5.84 करोड़ रुपए रही है।

## 2.16 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार भारी उद्योग विभाग के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुबंध-X में दी गई है।



## उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 3.1 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के एक सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 5.4.2003 को किया गया था। सम्मेलन में समझौता ज्ञापन और 'स्कोप' पुरस्कार वितरित किए गए थे।
- 3.2 जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को विनिवेश द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित किया गया था। धारक कंपनी भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा धारित इसके 72% की इक्विटी को कार्यनीतिक भागीदार को हस्तान्तरित करने के लिए दिनांक 29 अगस्त, 2003 को लेन-देन संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 3.3 इस विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई) को नीदरलैंड मेजरमेंट इंस्टीट्यूट (एनएमआई), दोरदेश, नीदरलैंड से शीर्ष फ्लो विशेषज्ञों के दल द्वारा आईएसओ/आईईएस 17025: 1999 के अनुसार "क्लोज्ड लूप एयर टेस्ट फेसिलिटी (सीएलएटीएफ)" के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।
- 3.4 फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड में दिनांक 22-24 सितम्बर, 2003 के बीच "हाइड्रोकार्बन प्रवाह मापन" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत और विदेश से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से फ्लो विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्र में भाग लिया। फ्लो उत्पादों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।
- 3.5 एफसीआरआई ने अस्थायी मापन के लिए उच्च दाब, उच्च तापक्रम मल्टीफेज फ्लोमीटर की डिजाइन और विकास के लिए 74.30 लाख रुपए के एक परियोजना प्रस्ताव को प्रायोजित करने हेतु बीएआरसी और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 3.6 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से संबंधित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
- (i) गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित प्रधानमंत्री के 17 श्रम पुरस्कारों में से प्रधानमंत्री के 4 श्रम पुरस्कार जीते।
- (ii) भारत से बाहर विद्युत उत्पादन, विद्युत पारेषण और परिवहन परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय ईपीसी संविदाकार "स्कोडाएक्सपोर्ट" के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- (iii) मथुरा तेलशोधनशाला परिसर में एक ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन से 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया।
- (iv) प्रत्येक 250 मेगावाट की यूनिट वाली छत्तीसगढ़ में 500 मेगावाट की कोरबा (पूर्व) थर्मल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए चीनी कंपनियों से सख्त प्रतिस्पर्धा के सामने 1700 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।
- (v) नई दिल्ली में दिनांक 5 से 8 फरवरी, 2003 तक आयोजित इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर शो-आईआईटीएफ 2003 में अपने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों यथा विद्युत, उद्योग, पारेषण, परिवहन, दूरसंचार, तेल और गैस और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 'एकल स्रोत से पूर्ण समाधान' प्रदान करने में अपनी दक्षता प्रदर्शित की।
- (vi) 2x500 मेगावाट के एनटीपीसी विंध्याचल एसटीपीएस के लिए 2125 करोड़ रुपए का बड़ा ठेका प्राप्त किया।
- (vii) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वीरसिंघपुर थर्मल विद्युत स्टेशन की 500 मेगावाट की यूनिट स्थापित करने के लिए 1589 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
- (viii) विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक समाधान और अभिनव प्रौद्योगिकी और भावी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित

समाधान प्रदान करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- (ix) वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई और एक्जिम बैंक द्वारा स्थापित सीआईआई-एक्जिम महत्वपूर्ण उपलब्धि सराहना प्रमाणपत्र जीता।
- (x) अपने औद्योगिक प्रणाली समूह (आईएसजी) के लिए डेट नॉर्स्क वेरिटाज (डीएनवी), नीदरलैंड द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित आईएसओ-14001 और ओएचएसएस-18001 प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
- (xi) स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं में अन्य कार्य करने के अतिरिक्त विद्युत संयंत्र चलाने और अनुरक्षण के लिए 50:50 के हिस्से सहित एक संयुक्त उपक्रम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संवर्धित करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- (xii) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा छोड़े गए इन्सेट 3ए और जीसेट-2 पर अंतरिक्ष श्रेणी के सौर पैनल को सफलतापूर्वक संस्थापित करने से एक बड़ा मानदंड प्राप्त किया।
- (xiii) ताइवान पावर कंपनी (टीपीसी) के बिहाई जल विद्युत संयंत्र में स्थापित किए जाने वाले 62.5 मेगावाट हाइड्रो टर्बाइन जेनरेटर के लिए ताइवान से जल विद्युत उपस्कर के लिए 40 करोड़ रुपए मूल्य का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया।
- (xiv) अपने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र प्रभाग के लिए प्रतिष्ठित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रमाणीकरण (ओएचएसएस-18001) पुरस्कार और प्रतिष्ठित आईएसओ 14001-पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली प्रमाणीकरण प्राप्त किया।
- (xv) प्रत्येक 500 मेगावाट के 2 यूनितों वाली नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की 1000 मेगावाट

कहलगांव सुपर थर्मल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए वैश्विक निविदा के माध्यम से 1412 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

- (xvi) भारत में सरकारी और निजी कंपनियों में लगातार तेरहवें वर्ष शीर्ष निर्यातक का पुरस्कार प्राप्त किया।
  - (xvii) राजस्थान में लिग्नाइट-आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 243 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
  - (xviii) कर्नाटक में 500 मेगावाट की बेलारी थर्मल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 1619 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।
  - (xix) लीबिया में स्थापित किए जा रहे 600 मेगावाट गैस टर्बाइन आधारित विद्युत संयंत्र के लिए 150 मेगावाट गैस टर्बाइन जेनरेटर के निर्यात से समुद्रपारीय बाजार में नया मानदंड प्राप्त किया।
  - (xx) वर्ष 2003-2004 में अब तक का उच्चतम 16,469 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया, जो कंपनी के लिए लगभग दो वर्षों का कुल कारोबार है।
- 3.7 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) ने समय से पूर्व बछाऊ अंजार वाटर पाइपलाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु गुजरात के मुख्यमंत्री से परियोजना चालू करने का पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त किया। ईपीआई ने निम्नलिखित बड़े ऑर्डर भी प्राप्त किए:
- (i) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से उनके नासिक संयंत्र में एक नए एसेम्बली कम्प्लेक्स तथा हैंगर कम्प्लेक्स के लिए 41 करोड़ रुपए मूल्य का प्रोजेक्ट प्राप्त किया।
  - (ii) वरिया क्षेत्रीय जलापूर्ति स्कीम, सूरत, गुजरात की डिजाइन तैयार करने; निर्माण और चालू करने के लिए 55.30 करोड़ रुपए मूल्य का टर्नकी ठेका प्राप्त किया।
  - (iii) यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र के लिए निष्पंदन, अवक्षेपण

और आहरण प्रणाली हेतु यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया से 96 करोड़ रुपए मूल्य का प्रोजेक्ट प्राप्त किया।

3.8 एचएमटी लिमिटेड के संबंध में मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- (i) राजकोट में दिनांक 29 मई से 2 जून, 2003 तक आयोजित 'एग्रोविजन-2003' के दौरान 65 अश्वशक्ति श्रेणी का ट्रैक्टर प्रारंभ किया। इस मॉडल की अद्वितीय विशेषता यह है कि चालक कैबिन में वातानुकूलक प्रदान किया गया है।
- (ii) एचएमटी चिनार वाचेज के एक दृष्टिहीन कर्मचारी, श्री वली मोहम्मद भट ने अपने विशिष्ट कार्यनिष्पादन, अभिनव योग्यता और उत्पादकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान तथा असाधारण साहस और सूझबूझ के लिए श्रमश्री पुरस्कार प्राप्त किया।
- (iii) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने हाईटेक विशेष प्रयोजन मशीन (एसपीएम) की आपूर्ति के लिए बीएआरसी, मुम्बई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- (iv) कंपनी ने 34 रेडिएशन शील्डिंग विंडोज (आरएसडब्ल्यू) के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) कलपक्कम, तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- (v) कंपनी ने भारतीय बाजार में उच्च गति के ट्रैक्टर का विनिर्माण करने और प्रारंभ करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के मैसर्स ट्रैक्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- (vi) कंपनी ने 'कॉर्प किसान फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम' प्रारंभ किया, जिसके लिए एचएमटी ने एचएमटी

ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को निम्न ब्याज दर पर सरल ऋण प्रदान करने हेतु कारपोरेशन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- (vii) एचएमटी लिमिटेड ने सड़क, बांध के निर्माण और खनन कार्यों आदि में प्रयोग के लिए 65 अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टर मॉडल 6522 पर निर्मित "एचएमटी वज्र" नामक अत्यधिक सक्षम, लचीले और, लागत प्रभावी अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रारंभ किया।
- (viii) श्रीमती डीवाई गिरीजम्मा, वरिष्ठ ऑपरेटर, एचएमटी (वाच) फैक्ट्री का प्रधानमंत्री के श्रम देवी पुरस्कार, 2003 के लिए चयन किया गया था।

3.9 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- (i) सीएम-एक्सएल और मैक्स एक्सएल के लिए बीएसएनएल से 22.86 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
- (ii) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश और गुजरात राज्यों से पहचान पत्रों के लिए 17.75 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
- (iii) जल प्रबंध प्रणाली के लिए सीएमसी, बंगलौर से 3.25 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
- (iv) अपतटीय इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ओएनजीसी से 7.42 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

3.10 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को "ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता रजत पुरस्कार, 2001-02" प्रदान किया गया।

3.11 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आरआईईएल) ने 12 करोड़ रुपए की लागत पर 3 महीने की रिकार्ड अवधि में पंजाब में 1000 पीसी-आधारित दुग्ध-संग्रहण स्टेशन की तैनाती पूरी की।

## सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यम

### 4.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एंड कंपनी औद्योगिक पंखे, चाय कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर सहित विद्युत उपकरणों आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के कार्य में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिए चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कंपनियां वर्ष 1986 में कंपनी का हिस्सा हो गई। ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल किया गया था। कंपनी रूग्ण है और उसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी और दो बड़ी सहायक कंपनियां अर्थात् दिशेरगढ़ पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड (अब डीपीएससी लिमिटेड के रूप में पुनः नामित) और टाइड वाटर ऑयल कंपनी भी शामिल है। कंपनी के बेल्टिंग प्रभाग को दिनांक 1.2.1999 से एक संयुक्त उद्यम कंपनी में बदल दिया गया है और नई कंपनी की 74% इक्विटी फीनिक्स एजी जर्मनी और 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास है। कंपनी ने वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में 97.96 करोड़ रुपए का उत्पादन किया। कुल लगभग 170 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ सरकार द्वारा कंपनी का व्यापक पुनर्गठन अनुमोदित कर दिया गया है। पूर्वनीति के अनुसार कम्पनी की विनिवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तथापि राष्ट्रीय न्यूनतम साझाकार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के आलोक में समीक्षा की जा रही है।

### 4.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी की स्थापना एंड्रयू यूल समूह के अधीन कंपनियों की मुद्रण और लेखन-सामग्री संबंधी आवश्यकता की

पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में की गई थी। यह एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हैं। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी का उत्पादन 9.25 करोड़ रुपए का रहा है। विनिवेश/संयुक्त उद्यम के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और इस समय यह अन्तिम चरण में है। पूर्वनीति के अनुसार कम्पनी की विनिवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तथापि राष्ट्रीय न्यूनतम साझाकार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के आलोक में समीक्षा की जा रही है।

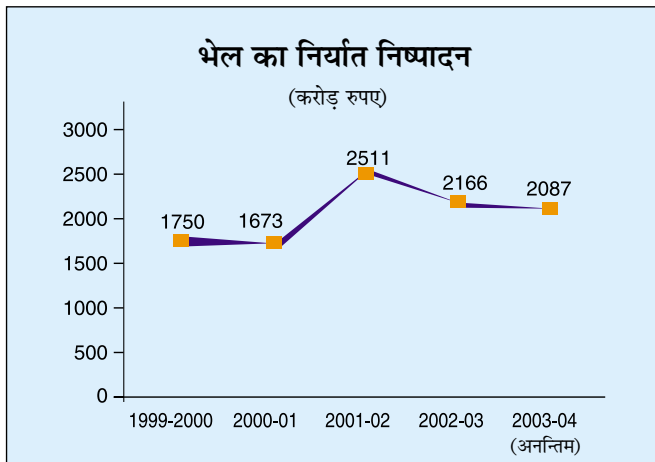
### 4.3 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। 'भेल' आज विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सभी प्रणालियों और उपकरणों की आपूर्ति करने वाली एकमात्र प्रमुख कंपनी है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 14 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केंद्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्र हैं। कंपनी को एक 'नवरत्न' सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में अभिज्ञात किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में 'भेल' के कार्यनिष्पादन के लिए इसे 'उत्कृष्ट' की श्रेणी में रखा गया है।



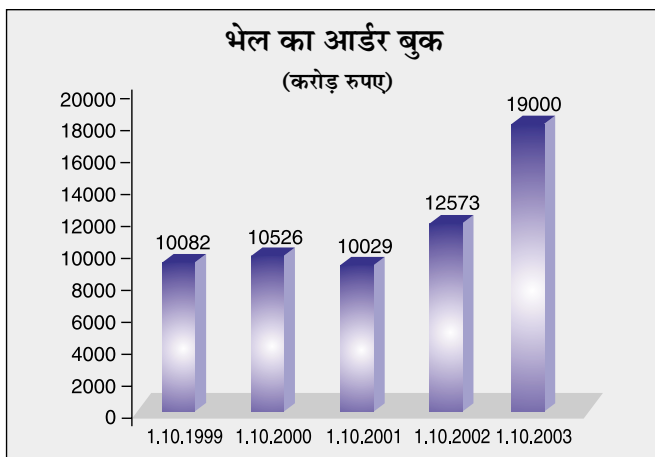
भेल द्वारा स्थापित कोटा थर्मल पावर संयंत्र

कंपनी ने कारोबार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए कई कदम उठाए हैं जहां इसके मौजूदा आधारभूत ढांचे, कौशल और क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे कुछ नए क्षेत्रों में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, उन्नत श्रेणी के गैस टर्बाइन, सेरालिन इंसुलेटर्स, कंगन वाली गढ़ाई, जल प्रबंध, सामग्री प्रहस्तन, प्रचलन और अनुरक्षण सेवाएं, सिमुलेटर्स और सेना के लिए उपस्कर और सेवाएं शामिल हैं।



कंपनी ने एक जर्मनी के मैसर्स सीमेन्स के साथ और दूसरा अमरीका के मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक के साथ दो संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। ये उद्यम क्रमशः ताप संयंत्रों के रख-रखाव/नवीकरण से संबंधित हैं।

वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी ने 8653 करोड़ रुपए का उत्पादन किया।



#### 4.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

बाहरी एजेंसियों के साथ अंतर इकाई सहसंबंध और बेहतर समन्वय द्वारा तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय प्रभावोत्पादकता लाने के प्राथमिक उद्देश्य से धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीवीयूएनएल) को वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था। इसकी निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं:

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल)

(अब बंद हो गया है)

(ख) आरबीएल लिमिटेड (अब बंद हो गया है)

(ii) भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

(iv) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड

(अब बंद हो गया है)

सहायक कंपनी (i) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड

(डब्ल्यूआईएल) अब बंद हो गया है।

(v) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(vi) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 से विनिवेश किया गया)

वर्ष 2003-2004 में धारक कंपनी की सभी प्रचालनरत सहायक कंपनियों (जेसप एंड) कंपनी को छोड़कर का कुल उत्पादन (अनन्तिम) 284.07 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.5 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को वर्ष 1976 में समामेलित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफ़ैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयां हैं। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स,

प्लांट्स एंड क्रॉसिंग, बोगियां, राख प्रहस्तन संयंत्र, कोयला प्रहस्तन संयंत्र आदि शामिल हैं। कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी के लिए बीआईएफआर द्वारा एक पुनरुद्धार योजना स्वीकृत की गई थी। कंपनी की 7 घाटा उठा रही रिफैक्टरी इकाइयां और जेलिघंम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद बंद कर दिया गया है।

संशोधित नीति के अनुसार, कम्पनी की विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। अब समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 176.92 करोड़ रुपए है।



बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा निर्मित कास्ट स्टील हाई स्पीड बोगी

#### 4.6 जेसप एंड कंपनी लिमिटेड

कंपनी उत्पादों की विविध श्रृंखला जैसे रेलवे रोलिंग स्टॉक, अर्थ मूविंग उपस्कर, व्यापक रेंज के क्रेन, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, हाइड्रॉलिक गेट, पेपर मशीनरी आदि की डिजाइन और विनिर्माण में लगी है। कंपनी का अगस्त, 2003 में महत्वपूर्ण भागीदार को अधिकांश इक्विटी प्रदान करके विनिवेश किया गया है। कंपनी अब सरकारी क्षेत्र का उद्यम नहीं रही है।

#### 4.7 ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स



ब्रेथवेट एण्ड कं. द्वारा विनिर्मित टैंक वैगन

और (iii) एंगस वर्क्स हैं, जो प्राथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यों के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर प्रहस्तन क्रेन, रेल-माउंटिंग डीजल लोको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट कार्टिंग मशीन और जूट उद्योग के लिए रोल फीडर्स आदि शामिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। कंपनी रूग्ण है और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। पूर्व नीति के अनुसार, कम्पनी की विनिवेश-प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तथापि, राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के आलोक में समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 65.44 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.8 भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) की स्थापना वर्ष 1979 में ब्रिटेनिया, मोकामा, बिहार और आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर, बिहार के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई थी। कंपनी के मुख्य उत्पादों में रेलवे वैगन, स्क्रू पाइल ब्रिज, इस्पात ढांचे, ग्रे आयरन कास्टिंग आदि शामिल हैं। कंपनी को बीआईएफआर भेजा गया है क्योंकि यह रूग्ण हो गई है। संशोधित नीति के अनुसार विनिवेश की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 11.91 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.9 ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड कंपनी के रूप में वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी के निर्माण का कार्य करती हैं। बीबीजे ने रस्सों वाले लंबे सड़क पुलों के निर्माण की आधुनिक तकनीकी हासिल कर ली है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। कंपनी के प्रस्तावित विनिवेश की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी का कुल कारोबार 29.80 करोड़ रुपए रहा है।

#### 4.10 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकमुश्त और टर्नकी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से निम्नलिखित सहायक कंपनियों के कार्यकलापों को एकीकृत, अनुवीक्षण और समन्वित करने के मुख्य उद्देश्य से धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
4. रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद

वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान सभी सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 524.83 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.11 भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र पेट्रोरसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूंजीगत साज-सामान की आपूर्ति के लिए की गई थी।

कंपनी के तीन प्रभाग नामतः प्रोसेस प्लांट डिजाइन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिजाइन हैं। विद्यमान सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए कंपनी ने विश्व की विख्यात कंपनियों से तकनीकी सहायता के साथ वायु और गैस पृथक्करण संयंत्रों के विनिर्माण, औद्योगिक बॉयलरों की डिजाइन और विनिर्माण, प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रणाली पैकेज आदि जैसी अनेक स्कीमों का विविधीकरण किया है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के लिए कंपनी का उत्पादन 41.05 करोड़ रुपए रहा है।



बी.एच.पी.वी. द्वारा विनिर्मित 225 मी.ट. यूरिया रियेक्टर

#### 4.12 भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड

भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रों की विभिन्न किस्म के पंपों और कंप्रेसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर

को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कंपनी की पुनरुद्धार योजना सफल नहीं रही है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा संयुक्त उद्यम भागीदार खोजने का प्रयास आरंभ किया गया है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी ने 47.26 करोड़ रुपए का उत्पादन किया।

#### 4.13 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) प्रारंभ में बालमेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 1.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के निवेश के माध्यम से बीएंडआर एक सरकारी कंपनी बन गई। इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986 में पेट्रोलियम मंत्रालय से इस विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कंपनी के प्रचालन में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, प्रशीतन टावरों के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, तेलशोधन शालाओं, उर्वरक, रसायन, इस्पात, अल्युमीनियम आदि के लिए संपूर्ण संयंत्रों



बीएंडआर द्वारा चालू आईपीसीएल, नागोथाने में गैस क्रैकिंग यूनिट

का यांत्रिक निर्माण कार्य शामिल है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 403.75 करोड़ रुपए रहा है।

#### 4.14 रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक-एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कंपनी वर्ष 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में इस्पात के ढांचे ट्रांसमिशन लाइन के टावर, औद्योगिक मशीनरी, रसायन मशीनरी, प्रशीतन उपस्कर आदि शामिल हैं। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा वर्ष 1995 में स्वीकृत पुनरुद्धार योजना विफल रही है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने इसे बंद करने का आदेश पारित किया। एएआईएफआर के समक्ष अपील दाखिल की गई हैं। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 24.81 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.15 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में समामेलित किया गया था। कंपनी प्राथमिक तौर पर इस्पात के भारी ढांचों जैसे विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिक्ल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि का विनिर्माण करती है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना विफल रही है और बीआईएफआर ने इसे बंद करने के आदेश पारित किए हैं। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान उत्पादन 0.49 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.16 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना प्रारंभ में कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई



थी। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) फरवरी, 1967 में एक सरकारी कंपनी बनी। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढांचे, ट्रांसमिशन लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना के कार्य में लगी है। पूर्व नीति के अनुसार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। तथापि, राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के आलोक में समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 7.47 करोड़ रूपए का रहा है।



टीएसपीएल द्वारा चमेरा परियोजना के लिए गैन्ट्री क्रेन और ब्लक हेड एमरजेंसी होइस्ट

#### 4.17 हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं।

कंपनी व्यापक मात्रा में उन्नत दूरसंचार केबल और तारों का विनिर्माण करती है और रेलवे, रक्षा, संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा जा रहा है। विभाग एचसीएल के भविष्य से संबंधित उपलब्ध विकल्पों की जांच कर रहा है।

वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 104.86 करोड़ रूपए का रहा है।



हिंदुस्तान केबल लिमिटेड के हैदराबाद प्लांट में जेलीपूरित केबल की आर्मरिंग

#### 4.18 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य से दिसम्बर, 1958 में समामेलित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां हैं, यथा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीवी) और फाऊंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिप्लर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स सहित हैवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 149.39 करोड़ रूपए का रहा है।

#### 4.19 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। यह कंपनी मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी

मशीनरी के विनिर्माण में लगी है। उसकी देश भर में कई इकाइयां हैं।

कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठाती रही है। सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नए अलग-अलग सहायक कंपनियों में बदलने और उन सहायक कंपनियों में इक्विटी का विनिवेश करके संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है। कंपनी को ट्रेक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए धारक कंपनी एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के लिए विनिवेश करने/संयुक्त उद्यम का गठन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

एचएमटी के ट्रेक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में 25 अश्वशक्ति के ट्रेक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारंभ किया परंतु तत्पश्चात इसने 75 अश्वशक्ति तक के ट्रेक्टर विकसित किए।

इस समय कंपनी की भारत में तीन ट्रेक्टर विनिर्माण इकाइयां हैं जो पिंजोर, हरियाणा, मोहाली, पंजाब और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में स्थित हैं। इसका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास केंद्र हैं।

वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान एचएमटी धारक कंपनी (ट्रेक्टर्स प्रभाग) का उत्पादन 129.35 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.20 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एचएमटी लिमिटेड ने “एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड” नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में समामेलित किया है।

इसकी पांच स्थानों पर अपनी विनिर्माण इकाइयां हैं, जो मशीन टूल्स के विशेष समूह में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। इसका बिक्री और सेवा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। एचएमटी-एमटी लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकाइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी का उत्पादन 178.34 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.21 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

भारत में घड़ियों का निर्माण प्रारंभ करने वाली प्रथम कंपनी, एचएमटी लिमिटेड ने ‘एचएमटी वाचेज लिमिटेड’ नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का वर्ष 1999 में समामेलन किया है। यह मैकेनिकल और क्वार्ट्ज एनालॉग घड़ियों का विनिर्माण करती है।

कलाई घड़ियों का विनिर्माण जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग के अधीन वर्ष 1962 में एचएमटी की विविधीकरण कार्यनीति के एक भाग के रूप में बंगलौर में प्रारंभ किया गया था

एचएमटी वाचेज लिमिटेड की बंगलौर, तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं जबकि विपणन मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के सभी वर्गों सस्ती से महंगी तक और नौजवानों से लेकर बड़ों तक के लिए सेवा प्रदान करती है। एचएमटी ब्रांड की भारतीय बाजार में काफी अधिक ब्रांड हिस्सेदारी है।

इसके ब्रांड की देश में अग्रणी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में भारतीय ब्रांडों में लगातार सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। पूर्व नीति के अनुसार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में इस मामले की पुनः जांच की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 25.65 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.22 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड ने वर्ष 2000 में “एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड” को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में समामेलित किया। यह पुरुषों के लिए मैकेनिकल घड़िया बनाती है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड में जम्मू में पंजीकृत कार्यालय सहित श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में एक एकत्रण (असेम्बली) इकाई शामिल है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला में 13 मॉडल हैं। एचएमटी घड़ियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता उपभोक्ता के लिए प्रमुख आकर्षण और बिक्री की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड अपने उत्पादों का विपणन एचएमटी वाचेज लिमिटेड के व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से करता है।

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के पास प्रतिवर्ष 5 लाख घड़ियों के विनिर्माण की क्षमता है। पूर्व नीति के अनुसार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत नई नीति के आलोक में समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी का उत्पादन 1.98 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.23 प्रागा टूल्स लिमिटेड

प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), सिकन्दराबाद को मूलतः एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्ष 1943 में समामेलित किया गया था। यह कंपनी वर्ष

1959 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। फरवरी, 1988 में जब इसकी 51% शेयर पूंजी एचएमटी लिमिटेड के नाम हस्तांतरित की गई तब यह उसकी सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स अर्थात् सीएनसी कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सीएनसी मिलिंग मशीन, थ्रेड रोलींग मशीन, जिंग बोरिंग मशीन और सीएनसी जिग बोरिंग मशीन आदि का निनिर्माण करती रही है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान उत्पादन 8.12 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.24 एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 23.60 करोड़ रुपए रहा है।



एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड द्वारा विनिर्मित बियरिंग्स के उत्पाद रेंज

#### 4.25 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख

वस्तुओं में यंत्र और उपकरण, घड़ियां और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें अफ्रीका, रूस, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 29.58 करोड़ रुपए हैं।

#### 4.26 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) की स्थापना 1964 में गयी थी। इसकी तीन उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान) और पलक्कड़ (केरल) में हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी में. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधारित एवं डिजिटल वितरित नियंत्रण प्रणाली, उन्नत ट्रांसमिटर्स, दोष सहाय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेत प्रणालियों और दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के कार्य में लगी है।

कंपनी रूग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर ने मार्च, 1999 में एक पुनरूद्धार पैकेज स्वीकृत किया है, जिस पर अमल किया जा रहा है। पुनरूद्धार योजना के अनुसार, सरकार ने 66 करोड़ रुपए की नई राशि जारी कर दी है और 42.98 करोड़ रुपए का वित्तीय पुनर्गठन किया है। सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा टेलीफोन एक्सचेंजों की आवश्यकता के 10 प्रतिशत की सीमा तक आदेशों के आरक्षण का अनुमोदन कर दिया है। पूर्व नीति के अनुसार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। तथापि, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान आईएलके का उत्पादन 139.02 करोड़ रुपए रहा है।

#### 4.27 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के संयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क

टेस्टर (ई.एम.टी.) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों, डेरियों, दुग्ध शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी ने सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपनी उत्पादन रेंज का विविधीकरण किया है। अपने चमकदार कार्य-निष्पादन के कारण इस सरकारी उद्यम ने 'मिनिरल' का स्तर प्राप्त किया है। पूर्व नीति के अनुसार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। तथापि, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) में कंपनी का उत्पादन 44.05 करोड़ रुपए रहा है।

#### 4.28 नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल) का गठन जून, 1957 में उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के अधीन एक विभागीय कार्यशाला नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की सम्पत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण से हुआ था। कंपनी रात में देखने में काम आने वाले उपकरणों सहित गैस मीटर, कैमरा, प्रेशर व वैक्यूम गेज सहित सर्वेक्षण के लिए कई प्रकार के ऑप्टिकल और आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन और व्यापार करती है। कंपनी रूग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर द्वारा नवम्बर, 1999 में स्वीकृत पुनरूद्धार योजना के अनुसार, सरकार ने निधियों के लिए निवेश के रूप में 17.96 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। तथापि, कंपनी का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक है। वर्ष 2003-04 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 3.62 करोड़ रुपए रहा है। विभाग एनआईएल के भविष्य से संबंधित उपलब्ध विकल्पों की जांच कर रहा है।

#### 4.29 स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) का गठन सितम्बर, 1972 में हुआ

था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का उत्पादन होता है। कंपनी रूग्ण होने के कारण बीआईएफआर को संदर्भित की गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल चूल परिवर्तन किया है और लगातार पिछले तीन वर्षों में कंपनी ने लाभ दर्शाया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार होने से यह बीआईएफआर के विचार क्षेत्र से बाहर आ गई है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी ने 157.15 करोड़ रुपए का उत्पादन किया है।

#### 4.30 भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमिटेड

भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) की स्थापना नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड से दुर्गापुर स्थित ऑप्टिकल ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर अप्रैल, 1972 में की गई थी। कंपनी ऑप्टिकल ब्लैक फिल्ट बटन, ऑप्टिकल ग्लास, खिड़कियों के लिए विकिरण रोकने वाले शीशे और रक्षा, परमाणु और अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष किस्म का ऑप्टिकल ग्लास बनाने वाली कंपनी है। कंपनी रूग्ण हो चुकी है और बीआईएफआर को भेजी गई थी। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी का प्रचालन मार्च, 2003 से बंद हो गया है।

#### 4.31 सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और क्षेत्रीय असंतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से जनवरी, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां कार्य कर रही हैं, जो छत्तीसगढ़ में मन्थार, अकलतारा; और नयागांव, मध्य प्रदेश; कर्नाटक में कुरकुंटा; असम में बोकाजन; हिमाचल प्रदेश में राजबन; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तेंदूर; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है।

धन की अत्यंत कमी, आधारभूत ढांचे, खास तौर पर बिजली की कमी के कारण कंपनी के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसकी 10 में से 7 इकाइयां विभिन्न कारणों से प्रचालन में नहीं हैं। कंपनी दिनांक 8.8.1996 को रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था। विधिवत विचार के बाद बीआईएफआर ने सीसीआई को श्रम मंत्रालय के पास ऐसी गैर-प्रचालक इकाइयों को बंद करने के उनको अनुमोदन के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, बीआईएफआर के निर्देशानुसार ओए ने चालू प्रतिष्ठान आधार पर संपूर्ण रूप से सीसीआई अथवा उसकी इकाइयों को अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से बिक्री पूरा करने हेतु एक मर्चेन्ट बैंकर नियुक्त किया है। चालू इकाइयों में वर्ष 2003-04 (अनन्तिम) के लिए उत्पादन 132.16 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.32 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

1970 में गठित हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) कागज, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है।

एचपीसी एक धारक कंपनी है और इसकी नीचे दिए गए अनुसार 2 सहायक कंपनियां और 2 प्रमुख समन्वित कागज व लुगदी मिलें हैं।

##### एचपीसी की सहायक कंपनियां

- क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)
- ख) नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

##### एचपीसी की इकाइयां

- (i) नौगांव पेपर मिल्स (एन पी एम)
- (ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

वर्ष 2003-2004 के दौरान कंपनी (एनपीएम और सीपीएम) का उत्पादन 569.81 करोड़ रुपए रहा है।

#### 4.33 नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार 5.22 प्रतिशत शेयरों की स्वामी है। वित्तीय पुनर्गठन के कारण कंपनी बीआईएफआर के दायरे से बाहर आ गयी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति, आधारभूत ढांचे की कमी और बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण पुनरूद्धार योजना पर अमल न हो सकने से यह पुनः रूग्ण हो गई। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है।

#### 4.34 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलतः एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के निर्माण में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। कंपनी ने 52.20 करोड़ की लागत से एक डी-इंकिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना आरंभ की है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है और वन्य संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान उत्पादन 250.94 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.35 हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) की स्थापना 1960 में चलचित्र उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा बलों और फोटोग्राफरों को क्रमशः फोटोग्राफिक फिल्म, एक्स-रे फिल्म और विशेष फोटोग्राफिक सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। कंपनी के दो उत्पादन संयंत्र-मुख्य

फैक्ट्री ऊटकमंड में और एक संयंत्र चेन्नई के पास अम्बातूर में हैं। एचपीएफ ने 1967 में उत्पादन आरम्भ किया। कंपनी समन्वित उत्पादन और जम्बों कन्वर्जन, दोनों का काम करती है। समन्वित उत्पादन से बनायी जाने वाली चीजों में सिने फिल्म पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म, फोटोग्राफी का कागज और शौकिया फोटोग्राफी करने वालों के लिए श्वेत-श्याम फिल्मों के रॉल शामिल हैं। कंपनी ने एक परियोजना बनायी है, जिसके अंतर्गत पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्मस का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी रूग्ण है तथा उस बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 28.43 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.36 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

वर्ष 1959 में स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) अपनी तीन इकाइयों खारागोडा (गुजरात), मंडी (हिमाचल प्रदेश) और रामनगर (उत्तर प्रदेश) में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का



खारागोडा (गुजरात) में हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का ब्रोमीन संयंत्र

उत्पादन करती है। कंपनी रूग्णावस्था में होने के कारण बीआईएफआर के विचाराधीन है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान इसका उत्पादन 6.96 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.37 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और बाकी 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अंशदान किया गया है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल का नमक बनाने के साथ नमक पर आधारित रसायनों का निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 6.20 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.38 नेपा लिमिटेड

नेपा लिमिटेड (एनईपीए) को पहले नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्टूबर, 1949 में राज्य सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस तरह यह केन्द्र सरकार का सरकारी उद्यम बन गई। कंपनी कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्णावस्था में है और बीआईएफआर के विचाराधीन है। विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया और 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक इक्विटी की रणनीतिक बिक्री के अलावा सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इत्यादि का अनुमोदन कर दिया है। पूर्व नीति के अनुसार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में इसकी समीक्षा की जा रही है।

वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 38.15 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.39 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्वेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबड़ मैनुफैक्चर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में समामेलित किया गया था। इस कंपनी की तीन प्रचालन इकाइयां इस प्रकार हैं: (1) काकीनाड़ा में टायर डिवीजन; (2) टांगड़ा में औद्योगिक रबड़ उत्पाद डिवीजन; और (3) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में रीक्लेम्ड रबड़ इकाई। इसके द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों में मोटर वाहनों के टायर और ट्यूब, नायलॉन कन्वेयर बैल्ट, होस, वी बैल्ट और फैन बैल्ट आदि शामिल हैं। बाद में तत्कालीन अविभाजित चेकोस्लोवाकिया की टेक्नो एक्सपोर्ट के तकनीकी सहयोग से 6.31 लाख टायर और ट्यूब के निर्माण की वार्षिक क्षमता वाली एक आधुनिकीकरण तथा विस्तार परियोजना पूरी की गयी। कंपनी रूग्ण है और बीआईएफआर को भेजी गई है। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आलोक में कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का उत्पादन 144.88 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.40 भारत लैडर कारपोरेशन लिमिटेड

भारत लैडर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी) का गठन मार्च, 1976 में हुआ था, ताकि कंपनी चमड़े के सामान और जूतों आदि की खरीद और बिक्री जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा प्रोत्साहन और विकास संबंधी कार्य कर सके। कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के प्रयास असफल रहे हैं। इस बीच, कंपनी के सभी कर्मचारियों ने सरकार की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ ले लिया है। बीएलसी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा

433 के अधीन कंपनी को बंद करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दाखिल की है।

#### 4.41 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईपीआई) परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसका गठन 1970 में हुआ था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनात्मक इंजीनियरी सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2001 में कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के बाद



ई.पी.आई. लि., द्वारा निर्मित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)

कंपनी में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और लाभ अर्जित किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के आलोक में कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 400.78 करोड़ रुपए का रहा है।

#### 4.42 नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनआईडीसी) की स्थापना सरकार ने 1954 में की थी। कंपनी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना, औद्योगिक बस्तियों, जल आपूर्ति एवं शोधन, पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, औद्योगिक परियोजनाओं और कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास के क्षेत्र में परामर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराती रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रही है। चूंकि, यह कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है, इसलिए इसे बीआईएफआर को नहीं भेजा जा सकता। कंपनी को संयुक्त उद्यम में बदलने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने वीआरएस का विकल्प चुना है। कंपनी को बंद करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्रवाई आरंभ की गई है।



## भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र

### 5.1 भारी विद्युत उद्योग

भारी विद्युत उद्योग मूलतः विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण उपस्कर शामिल करता है। इनमें टर्बो जेनरेटर्स, बॉयलर, विभिन्न प्रकार के टर्बाइन, ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और अन्य संबद्ध मदें शामिल हैं। विद्युत उत्पादन उपस्कर की मांग मुख्यतः विद्युत विकास कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। दसवीं और ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य लगभग 1,00,000 मेगावाट है अर्थात् प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मेगावाट की वृद्धि है। स्थापित किए जाने वाले नए विद्युत संयंत्रों से भारी विद्युत उपस्कर के लिए पर्याप्त मांग उत्पादित करने की प्रत्याशा है।

ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर आदि जैसे विद्युत उपस्कर का प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कुछ मुख्य क्षेत्र जहां इनका प्रयोग किया जाता है वे परमाणु विद्युत स्टेशन सहित विद्युत उत्पादन करने वाली करोड़ों रुपए की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स, रसायन संयंत्र, एकीकृत इस्पात संयंत्र, अलौह धातु इकाइयां आदि हैं। यह उद्योग वर्तमान प्रौद्योगिकी का उन्नयन करता रहा है और यह अब निर्यात बाजारों के लिए भी टर्नकी संविदाएं लेने में सक्षम है। उद्योग को अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ विदेशी सहायोग की भी अनुमति है।

भारी विद्युत उपस्कर के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार स्थापित किया जा चुका है और उद्योग की मौजूदा संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष थर्मल का 4500 मेगावाट, जल विद्युत का 1345 मेगावाट और गैस आधारित विद्युत उत्पादन उपस्कर

का लगभग 250 मेगावाट है। भारतीय भारी विद्युत उद्योग परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित उपस्कर के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए भी सक्षम है। देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में भारतीय उद्योग का वर्तमान हिस्सा लगभग 66% है।

भारी विद्युत उद्योग 400 केवी एसी और हाईवोल्टेज डीसी तक पारेषण और वितरण में काम आने वाले उपस्कर का विनिर्माण करने में सक्षम है। उद्योग ने 765 केवी की अगली उच्चतर वोल्टेज प्रणाली में पारेषण के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया है और 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, सीटीएस, सीवीटी, बुशिंग और इन्सुलेटर आदि की आपूर्ति करने के लिए अपनी विनिर्माण सुविधाओं का उन्नयन किया है। इस्पात संयंत्रों, पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्सों और ऐसे ही अन्य भारी उद्योगों में काम आने वाले बड़े विद्युत उपस्कर का विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है।

भारी विद्युत उद्योग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों की स्थिति के बारे में एक प्रास्थिति रिपोर्ट नीचे दी गई है:-

### 5.2 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

विभिन्न प्रकार के टर्बाइनों, जैसे औद्योगिक टर्बाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइनों के विनिर्माण की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 7000 मेगावाट से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल, जिसकी स्थापित क्षमता सबसे अधिक है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी ऐसी इकाइयां हैं, जो बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए स्टीम और हाइड्रो टर्बाइनों का निर्माण कर रही है। भेल के निर्माण दायरे में 500 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले

स्टीम टर्बाइन शामिल हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाकर 660 मेगावाट करने की योजना है। भेल 255 मेगावाट (आईएसओ) तक क्षमता वाली गैस टर्बाइन बनाने की भी क्षमता रखता है। 'भेल' ने 210 मेगावाट और 250 मेगावाट थर्मल सेट के लिए एरोपवायल ब्लेडेड रेडियल फैन विकसित किया है, जो पारम्परिक सीधे ब्लेड वाले फैन से अधिक सक्षम है।

भारत में विनिर्मित एसी जेनरेटर अंतर्राष्ट्रीय एसी जेनरेटर के समान हैं, जो निष्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करते हैं। घरेलू विनिर्माता 0.5 केवीए से 25000 केवीए और उससे ऊपर विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के साथ एसी जेनरेटर के विनिर्माण में सक्षम है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 1012.81 करोड़ रुपए और 377.61 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष के दौरान निर्यात में लगभग 10% की वृद्धि हुई है।

### 5.3 बॉयलर

'भेल' देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता (60% हिस्से सहित) है और यूटीलिटी बॉयलरों और औद्योगिक बॉयलरों के अतिरिक्त सुपर थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए बॉयलर के विनिर्माण के लिए इसके पास क्षमता है। घरेलू उद्योग के पास बॉयलरों की देशी आवश्यकता/मांग को पूरा करने की क्षमता है। भारतीय उद्योग अपनी प्रौद्योगिकी का निरंतर उन्नयन कर रहा है और बेहतर उत्पादों का उत्पादन कर रहा है। 'भेल' ने 110 और 210 मेगावाट थर्मल विद्युत स्टेशनों के लिए उपयुक्त बॉयलर फीड पम्प का उन्नयन किया है। उन्नयन किए गए पम्पों में सरल अनुरक्षणीयता, वर्धित विश्वसनीयता है और उनकी बेहतर क्षमता है। उन्होंने इस्पात संयंत्रों में ब्लास्ट फर्नेस की गैस, जो अन्यथा बर्बाद होती है, के लिए 65 टन प्रति घंटे बॉयलर के लिए ब्लास्ट फर्नेस गैस प्रज्वलन प्रणाली भी विकसित की है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 5.82 करोड़ रुपए और 61.66 करोड़ रुपए का था। वर्ष के दौरान निर्यातों में 50% की वृद्धि हुई है।

### 5.4 ट्रांसफॉर्मर

उद्योग अत्याधुनिक उपस्कर प्रदान करने की क्षमता के साथ देश के विद्युत क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की आवश्यकता पूरी करने की लिए सुसज्जित है। उद्योग के पास आरईसी रेटिंग के 25/53/100 केवीए और अतिरिक्त 400 केवी, 600 एमवीए की हाईवोल्टेज रेंज सहित विद्युत और वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संपूर्ण रेंज के विनिर्माण की क्षमता है। फर्नेस, रेक्टिफायर्स विद्युत ट्रेक्ट आदि के लिए अपेक्षित ट्रांसफॉर्मरों की विशेष किस्मों तथा सीरिज और शन रिएक्टरों और साथ ही 500 केवी तक एचबीडीसी ट्रांसमिशन का विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 881.64 करोड़ रुपए और 560.77 करोड़ रुपए रहा है।

### 5.5 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

भारत में बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम से लेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड (एसएफ 6) तक सभी रेंजों के सर्किट ब्रेकरों का निर्माण ग्राहकों की खास जरूरतों के अनुरूप किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादों के रेंज में 240 वोल्ट से 800 के. वोल्ट तक की समग्र वोल्टता रेंज शामिल है। स्विचगियर और कंट्रोल गियर, मिनिअर सर्किट ब्रेकर्स (एमसीबी), एयर सर्किट ब्रेकरों, स्विचों, रीवायरबेल फ्यूजों और हाई रपचर कैपेसिटी (एचआरसी) फ्यूजों तथा उनके संबंधित फ्यूज बेस, होल्डर्स और स्टार्टर्स का निर्माण किया जाता है। 'भेल' ने पारेषण लाइनों की विद्युत अंतरण क्षमता बढ़ाने और पारेषण हानियों को कम करने के लिए फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) लोकप्रिय रूप से ज्ञात थाइरेस्टर कंट्रोल रिएक्टर वाली एक नई श्रृंखला प्रतिपूर्ति स्कीम विकसित की है। डिजाइन और

इंजीनियरी के क्षेत्र में उद्योग प्रतिस्पर्धा है क्योंकि देश में उपलब्ध कौशल संबंधी सेट अपेक्षतया सस्ते हैं।

वर्ष 2002-2003 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 882.69 करोड़ रुपए और 497.63 करोड़ रुपए का रहा था।

### 5.6 विद्युत भट्ठी

विद्युत भट्ठियों का प्रयोग फोर्जिंग और फाउंड्री, मशीन टूल्स, आटोमोबाइल आदि धात्विक और इंजीनियरी उद्योगों में किया जाता है। इन उत्पादों के उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल कर ली गई है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान आयात और निर्यात क्रमशः 31.90 करोड़ रुपए और 20.49 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2002-2003 की तुलना में वर्ष के दौरान निर्यात में 33% की वृद्धि हुई है।

### 5.7 शंटिंग लोकोमोटिव

शंटिंग लोकोमोटिव का प्रयोग रेलवे, इस्पात संयंत्रों, थर्मल विद्युत संयंत्रों आदि द्वारा स्थानीय/आंतरिक परिवहन सुविधाओं के लिए किया जाता है। अन्यो के अतिरिक्त 'भेल' की झांसी इकाई ऐसे लोकोमोटिव का विनिर्माण कर रही है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए संस्थापित क्षमता पर्याप्त है।

### 5.8 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

देश में लगभग 600 टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और सहायक उपकरणों के साथ छंटाई, रस्सी बनाने, धागों/फैब्रिक्स के प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित टेक्सटाइल मशीनरी के विनिर्माण में लगे हैं।

यह उद्योग वस्त्र विनिर्माता बहु-फाइबर करार (एमएफए) पश्च के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। टेक्सटाइल मशीनरी पर विकास परिषद ने इस



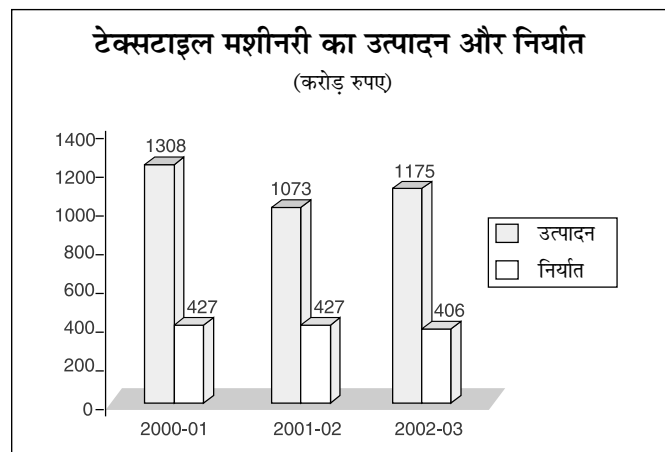
द्विन डिलीवरी ऑटो केवलर ड्रा फ्रेम एलडीए/2 स्पनिंग मशीन

उद्योग के उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय और साधन का सुझाव देने के लिए इस मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं वाला एक कार्यदल गठित किया है।

1500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका चालू उत्पादन तथा साथ ही निर्यात नीचे दिया गया है:



स्पनिंग मशीन कॉबर एल.के. 54



### 5.9 सीमेंट मशीनरी उद्योग

भारत में ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि कैलसिनेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर 7500 टीपीडी क्षमता वाले पूर्ण सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण किया जाता है। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों की डिजाइन यह ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पूर्ण ऊर्जा की खपत के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी को निर्माण को लिए वर्तमान में संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां कार्यरत है। उद्योग सीमेंट मशीनरी की घरेलू मांग पूरी करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। वर्तमान स्थापित क्षमता का मूल्य 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आंका गया है।

(करोड़ रुपए)

	2000-01	2001-02	2002-03
आयात	1.18	0.42	1.30
निर्यात	3.25	4.38	3.05

### 5.10 चीनी मशीनरी उद्योग

भारत विश्व में चीनी मशीनरी का एक शीर्षस्थ विनिर्माता है। भारतीय उद्योग 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक क्षमता वाले अत्याधुनिक डिजाइन के चीनी संयंत्रों की विनिर्माण की क्षमता रखता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण चीनी संयंत्र और संघटकों का विनिर्माण करने वाली 27 इकाइयां हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 200 करोड़ रुपए है। आयात और निर्यात निष्पादन नीचे दर्शाया गया है।

(लाख रुपए)

	2000-01	2001-02	2002-03
आयात	305	3.0	1.70
निर्यात	548	253	852

### 5.11 रबड़ मशीनरी उद्योग

इस उद्योग ने टायर ट्यूब क्यूरिंग प्रेस, ट्यूब स्प्लाइसर्स आदि के लिए सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध निर्यात

आदेश प्राप्त किए हैं और निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। ये मशीनें मुख्य रूप से टायर/ट्यूब उद्योग में काम आती है। देश में विनिर्मित उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्यूरिंग प्रेसिज, ट्यूब स्प्लाइसर्स, ब्लेडर क्यूरिंग प्रेसिज, टायर, माउल्ड्स, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नर सर्विस, बायर्स, कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल है। उच्च गति वाले कैलेंडरिंग लाइन विशेषकर हैवी अर्थमूविंग उपस्कर के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में अंतर है।

निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	2000-01	2001-02	2002-03
आयात	15.41	11.35	12.81
निर्यात	4.30	11.04	15.25

### 5.12 सामग्री प्रहस्तन उपस्कर उद्योग

सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं। विनिर्मित उपस्करों के रेंज में क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिपलोडर्स/अनलोडर्स, वैगन टिप्लर्स, फीडर आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की बढ़ती हुई और तेजी से परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

संगठित क्षेत्र में इकाइयों के अतिरिक्त, सामग्री प्रहस्तन उपस्करों और उसके संघटकों का विनिर्माण कर रहे लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में कमोवेश आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में सक्षम है।

### 5.13 ऑयल फील्ड उपस्कर

घरेलू विनिर्माता तटीय खुदाई के लिए ड्रिलिंग रिग्स का विनिर्माण कर रहे हैं। अपतटीय ड्रिलिंग, जैसे जैक-अप रिग्स आदि का देश में विनिर्माण नहीं किया जाता और इनका आयात कभी-कभी तो पुरानी दशा में किया जाता है। तथापि, अपतटीय प्लेटफार्मों और अन्य प्रौद्योगिकीय ढांचों का स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादकों में भेल, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक, बर्न एंड कम्पनी और लार्सन तथा टूब्रो शामिल हैं।

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया के जारी रहते उद्योग को सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे तेल की खोज, उत्पादन, शोध और विपणन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप ऑयल फील्ड और संबंधित उपकरणों की मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलाएंस इंडस्ट्रीज इनके प्रयोक्ता हैं।

### 5.14 धातुकर्म मशीनरी

वर्तमान में संगठित क्षेत्र में धातुकर्म मशीनरी की विभिन्न किस्मों के विनिर्माण में लगी 39 इकाइयां हैं। धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाऊंड्री उपस्कर और भट्टियां शामिल हैं।

देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर संयंत्रों, कोक ओवन्स, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, सतत कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन जैसे अधिकतर उपस्कर उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं।

इन उपस्करों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में वर्तमान उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। तथापि, लौह और अलौह धातु क्षेत्र में प्लांटों और औजारों के बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल है, जिसके लिए घरेलू विनिर्माताओं को आयातित जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रोसेस की जानकारी रखने वालों,

डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ परस्पर संपर्क की आवश्यकता है।

### निर्यात-आयात निष्पादन

(करोड़ रुपए)

	2000-01	2001-02	2002-03
आयात	386.49	191.80	244.18
निर्यात	128.90	126.60	267.96

### 5.15 खनन मशीनरी

वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं।

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयरर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं।

खनन उद्योग को खनन उपस्करों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी अधिकतर आपूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है। अत्याधुनिक उपस्करों के मामले में महत्वपूर्ण पुर्जों का आयात किया जाता है।

### 5.16 डेयरी मशीनरी उद्योग

वर्तमान में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी और निजीक्षेत्र दोनों में 16 इकाइयां हैं, जो डेयरी मशीनरी और उपस्करों के विनिर्माण में लगी हैं। हाल के वर्षों में मैसर्स एनडीडीबी द्वारा अनेक डेयरी संयंत्र चालू किए गए, जिनके लिए अधिकतर उपस्करों की आपूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की गई। वर्तमान में देशी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उपस्करों में स्टेनलेस स्टील डेयरी उपस्कर, इवेपेरेटर,

मिल्क रेफ्रिजरेटर और भंडारण टैंक, मिल्क और क्रीम डेओडोजर्स, सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एंजिटेडर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रे ड्रायर्स और हीट एक्सचेंजर (ट्यूबलर और प्लेट टाइप) आदि शामिल हैं। उनके मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे ड्रायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि किसी भी माइक्रोसरेविस के बचे रहने से बैक्टीरिया को सांस लेने या प्रजनन का आधार मिल सकता है।

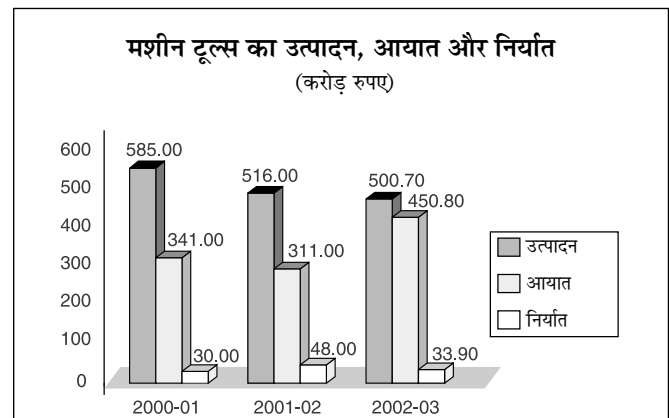
सेल्फ-क्लनिंग क्रीम-सेपरेटर, ऐसेप्टिक प्रोसेसिंग सिस्टम आदि जैसे प्रहस्तन उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल मौजूद है दही (योगार्ट) और परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए आवश्यक संयंत्र उपकरण से संबद्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में भी कमी पाई गई।

### 5.17 मशीन टूल्स उद्योग

भारत एक सुदृढ़ मशीन टूल उद्योग रखने वाले विश्व के कुछ विकासशील देशों में से एक है। यह न केवल घरेलू मांग पूरी करने बल्कि यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को भी साधरण प्रयोजन और मानक मशीन टूल्स का निर्यात करने की स्थिति में है। पिछले चार दशकों में भारत में मशीन टूल उद्योग ने सुदृढ़ आधार स्थापित कर लिया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 125 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु आनुषंगिक क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां भी हैं।

भारतीय मशीन टूल्स गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ विनिर्मित किए जाते हैं। अधिकांश प्रमुख विनिर्माता कम्प्यूटरीकृत संख्यांकित नियंत्रित मशीन (सीएनसी) टूल्स विकसित कर चुके हैं। उद्योग अब परम्परागत एवं एनसी/सीएनसी उच्च प्रौद्योगिकी वाली मशीन टूल्स का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर अधिक उपयुक्त डिजाइन वाले मशीन टूल्स के लिए अनुसंधान करता रहा है। इस क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और आयात की अनुमति भी दी गई है। विशेष प्रयोजन मशीनों और सीएनसी मशीन टूल की कुछ श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर है। इस अंतर को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के लिए मशीन टूल्स विनिर्माता संघ द्वारा प्रस्तुत उत्पादन, आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:



## आटोमोटिव उद्योग

### 6 आटोमोटिव उद्योग का पर्यावलोकन

6.1 आटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से तथा साथ ही भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक और अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कई भागों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण इस उद्योग का एक सुदृढ़ गुणक प्रभाव है और यह आर्थिक विकास का चालक बनने में सक्षम है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय आटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों: यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, तिपहिए, ट्रैक्टर आदि जैसे बहु-उपयोगी वाहनों का उत्पादन करके उस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

6.2 वर्ष 1982 तक मोटर कार के क्षेत्र में केवल 3 विनिर्माता-मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स, मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स और मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर्स थे। कम मात्रा होने के कारण यह लगातार पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाता रहा और विश्व उद्योग की तुलना से बाहर था। वर्ष 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड को तत्कालीन माडलों का भारी मात्रा में उत्पादन स्थापित करने के लिए जापान की सुजुकी के साथ सहयोग से सरकार द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1993 में लाइसेंस हटाए जाने के बाद 17 नए उद्यम स्थापित किए गए, जिनमें से 16 कार-विनिर्माता हैं। इस समय 12 यात्री कार विनिर्माता, 5 एमयूवी विनिर्माता, 9 वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता, दुपहिए के 12, तिपहिए के 4 और इंजनों के 5 विनिर्माता के अतिरिक्त 10 ट्रैक्टर विनिर्माता हैं।

6.3 उद्योग का 50,000 करोड़ से अधिक निवेश है। वर्ष 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग का कुल कारोबार 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। यह उद्योग 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा 1 करोड़ का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आटोमोटिव उद्योग का अंशदान 4.7% अनुमानित है।

### 6.4 संस्थापित क्षमता

वास्तविक रूप में आटोमोबाइल विनिर्माताओं ने वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 95 लाख वाहनों की सुदृढ़ विनिर्माण क्षमता स्थापित की है। भारत विश्व में दुपहिए का दूसरा, वाणिज्यिक वाहनों का पांचवा सबसे बड़ा विनिर्माता है और विश्व में ट्रैक्टरों का सबसे अधिक संख्या में विनिर्माण करता है। दो दशक पूर्व वाहनों के कुछेक माडलों वाले आपूर्तिकर्ता चालित बाजार के पास ग्राहकों के विकल्पों के अनुरूप अब 150 माडल हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल क्षेत्र की संस्थापित क्षमता निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	खण्ड	संस्थापित क्षमता (संख्याओं में)
1.	चार पहिए वाले	1,590,000
2.	दुपहिए और तिपहिए	7,950,000
3.	कुल योग	9,540,000

### 6.5 वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग का निष्पादन

#### 6.5.1 उत्पादन:

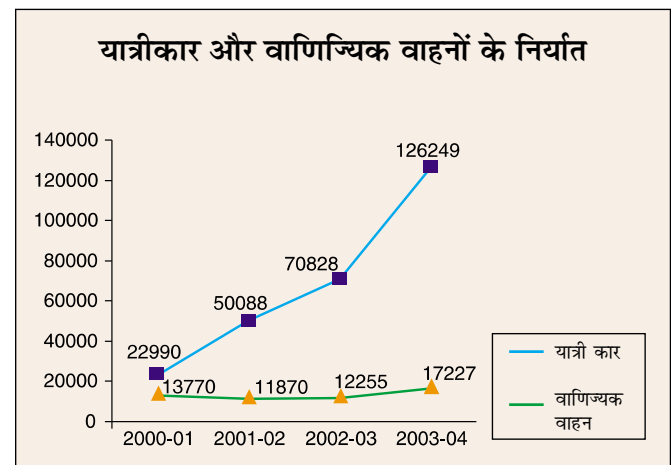
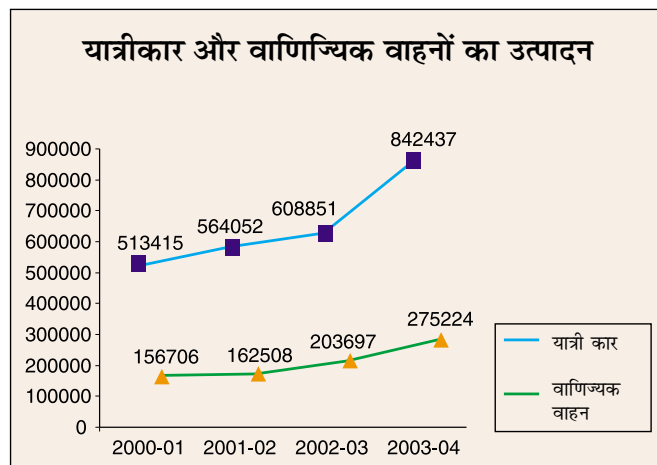
भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक आटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखता रहा है। समग्र आटोमोबाइल क्षेत्र ने वर्ष 2002-2003 में

18.60% की वृद्धि प्राप्त की। वर्ष 2003-2004 के दौरान उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 15.12% की वृद्धि दर

दर्ज की। वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(संख्या में)

क्रम सं. क्षेत्र का नाम	इकाइयों की संख्या	उत्पादन	
		2002-03	2003-04
1. वाणिज्यिक वाहन	9	203697	275224
2. कार	12	608851	842437
3. बहु-उपयोगी वाहन	5	114479	146103
4. दुपहिए	12	5076221	5624950
5. तिपहिए	4	276719	340729
<b>योग</b>	<b>42</b>	<b>6279967</b>	<b>7229443</b>



### 6.5.2 निर्यात

भारत का आटोमोटिव उद्योग अब संपूर्ण विश्व में वृद्धिकारी मान्यता प्राप्त कर रहा है और वाहनों तथा साथ ही संघटकों के निर्यात में शुरुआत की गई है। वर्ष 2003-2004 के दौरान कारों का निर्यात 100,000 का आंकड़ा पार कर गया। वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान निर्यातों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

### 6.6 वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में और सख्त बनाया गया, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारंभ की। भारत चरण-1 (यूरो-1 के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है और भारत अप्रैल, 2005 तक देश भर में भारत

(संख्या में)

क्रम सं. निर्यात	2002-03	2003-04
1. मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन	5638	8112
2. हल्के वाणिज्यिक वाहन	6617	9115
3. यात्री कार	70828	126249
4. बहु-उपयोगी वाहन	1177	3067
5. दुपहिए	179682	264669
6. तिपहिए	43366	68138
<b>योग</b>	<b>307308</b>	<b>479350</b>



चरण-II (यूरो-II के समतुल्य) मानदंड लागू करने के लिए कटिबद्ध है। ये मानदंड चार महानगरों में लागू हो चुके हैं। अप्रैल, 2005 से 7 महानगर भारत चरण-III (यूरो-III के समतुल्य) मानदंड अपनाने जा रहे हैं। नवीन उत्सर्जन मानदंडों की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय आटोमोबाइल उद्योग नए निवेश और प्रौद्योगिकीय जानकारियां अपना चुका है। उच्चतर सुरक्षा और उत्सर्जन मानक प्रणाली देश में उत्पादित और आयातित उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए पर्याप्त अवसंरचना की अपेक्षा करती है। देश में मौजूदा परीक्षण अवसंरचना आटोमोटिव उद्योग की भावी और उभरती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सीमित और बिल्कुल अपर्याप्त है। इसलिए सरकार ने उद्योग के घनिष्ठ सहायोग और समन्वय से मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन और देश में नई परीक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं।

## 6.7 आटोमोबाइल संघटक उद्योग

**6.7.1 पर्यावलोकन:** भारतीय आटोमोबाइल संघटक उद्योग ने वर्षों से देश के आटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। नब्बे के दशक से आटोमोबाइल उद्योग में उछाल से प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और निम्न मात्राओं की बहुलता के बावजूद विस्तार नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने और लचीलेपन के रूप में देश में आटोमोबाइल संघटक क्षेत्र का प्रभावशाली विकास हुआ है। भारत के उचित रूप से मूल्यनिर्धारित कुशल कार्यबल ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में देश द्वारा प्राप्त सुदृढ़ता के साथ संघटक उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए एक वातावरण निर्मित किया है। भारतीय आटोमोबाइल संघटक क्षेत्र को सॉफ्टवेयर क्षेत्र के बाद ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है जिसमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता है। आटोमोबाइल संघटक उद्योग 30,640 करोड़ रुपए के कुल कारोबार के साथ वाहन विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी मुख्य संघटकों का विनिर्माण कर रहा है

और इस प्रकार यह आटोमोटिव उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

**6.7.2 उत्पादन** भारतीय आटोमोबाइल संघटक क्षेत्र के पास आज 420 मुख्य संगठन हैं जो इस क्षेत्र के उत्पादन के 85% से अधिक का योगदान कर रहे हैं। वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल संघटक क्षेत्र के मुख्य आंकड़े निम्नानुसार हैं:

संकेतक	2002-03	2003-04
निवेश	12,500 करोड़ रु.	13,400 करोड़ रु.
उत्पादन	24,500 करोड़ रु.	30,640 करोड़ रु.
निर्यात	3,800 करोड़ रु.	4,550 करोड़ रु.
रोजगार	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति

भारतीय आटोमोबाइल संघटक क्षेत्र ने जापान, कोरिया, अमरीका और यूरोप से विश्व वाहन विनिर्माताओं के आगमन से बड़ी वृद्धि देखी है। इन ओईएम की प्रौद्योगिकीय रूपरेखा में विविधताओं के कारण यह क्षेत्र आज संघटकों की अनेक किस्मों का उत्पादन करता है। आज, भारत एशिया में मुख्य आटोमोबाइल संघटक केन्द्रों में से एक के रूप में उभर रहा है और उसके निकट भविष्य में वैश्विक आटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रत्याशित है।

### 6.7.3 निर्यात

वर्ष 2002-2003 में संघटक का निर्यात 800 मिलियन डालर का आंकड़ा पार कर चुका है। तथापि यह इस समय अनुमानित लगभग 1 खरब अमरीकी डालर के वैश्विक संघटक व्यापार के लगभग केवल 0.08% का प्रतिनिधित्व करता है। यह आगे आने वाले महत्वपूर्ण अवसरों का द्योतक है। कई निर्यात इकाइयां 5 भाग प्रति मिलियन (पीवीएम) से कम अस्वीकृत दर तक पहुंच गई हैं, जिनमें से कई ने शून्य पीपीएम प्राप्त कर लिया है। निर्यात के मोर्चे पर आटोमोबाइल संघटक उद्योग ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 2.5% की नगण्य वृद्धि की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 37% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की है।

पिछले वर्ष के दौरान 2775 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल निर्यात 3800 करोड़ रुपए का था।

वर्ष 2003-2004 के दौरान इस क्षेत्र के निर्यात में लगभग 20% की और वृद्धि हो गई।

## 6.8 ट्रेक्टर

6.8.1 वर्तमान में 16-20 के निम्न अश्वशक्ति से 50 और उससे अधिक के उच्चतर अश्वशक्ति वाले व्यापक रेंज के कृषि ट्रेक्टरों का विनिर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में 14 इकाइयां हैं। भारतीय ट्रेक्टर उद्योग का कुल निवेश 4500 करोड़ रुपए से अधिक और कुल कारोबार 6500 करोड़ रुपए है। यह उद्योग प्रत्यक्षतः 25,000 लोगों को और अप्रत्यक्षतः 1,00,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

6.8.2 इस उद्योग ने कुल 880 इकाइयों के उत्पादन से वर्ष 1961 में शुरुआत की। 1980 के दशक के पूर्वार्ध से ट्रेक्टरों की उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और वर्ष 1999-2000 में उत्पादन 2,66,385 के स्तर तक पहुँच गया। ट्रेक्टर उद्योग, जिसने वर्ष 1990-2000 के बीच 8% के सीएजीआर पर वृद्धि की, ने हाल के तीन वर्षों 2000 से 2003 तक मुख्यतः कुछ राज्यों में वर्षा के नही होने के कारण 36% की तीव्र गिरावट का अनुभव किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ट्रेक्टरों के उत्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	संख्या
1994-95	1,62,900
1995-96	1,91,149
1996-97	2,21,743
1997-98	2,56,258
1998-99	2,53,850
1999-00	2,66,385
2000-01	2,34,575
2001-02	2,15,000
2002-03	1,62,000

जबकि 31-40 अश्वशक्ति के रेंज में ट्रेक्टरों का उत्पादन लगभग 60% है वहीं यह 41 अश्वशक्ति और उससे अधिक के रेंज में 23% है। 30 अश्वशक्ति से कम वाली श्रेणी कुल उत्पादन का शेष 17% है।

### 6.8.3 प्रौद्योगिकीय क्षमता

यद्यपि ट्रेक्टर उद्योग ने उत्पादन संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की विख्यात विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी आयात करके प्रारंभ किया या फिर भी प्रौद्योगिकी को पूर्णतः आत्मसात कर लिया गया है। पिछले वर्षों से कुछ ट्रेक्टर विनिर्माताओं ने उच्च अश्वशक्ति श्रेणी के ट्रेक्टरों की विशिष्ट आवश्यकता पूरी करने के लिए आयातित संघटकों के साथ 75 अश्वशक्ति के उच्च अश्वशक्ति वाले ट्रेक्टरों का उत्पादन प्रारंभ किया है।

### 6.8.4 बाजार

परम्परागत रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ट्रेक्टर बाजार के प्रमुख राज्य हैं। मध्यप्रदेश आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में ट्रेक्टरों के नए बाजार तेजी से विकसित हो रहे हैं।

## 6.9 मिट्टी हटाने तथा भवन निर्माण मशीनरी

6.9.1 मिट्टी हटाने के उपकरण तथा निर्माण मशीनी उद्योग हमारे देश में आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता रहा है। यह उद्योग की प्रमुख विकासात्मक तथा संरचनात्मक योजनाओं जैसे कोयला तथा खनन, सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं, बंदरगाह, इस्पात, उर्वरक आदि के निकट रूप से संबद्ध है। ऐसी मशीनों के निर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले उपलब्ध नहीं थी। अतः यह आवश्यक हो गया था कि कोमत्सु, केटरपिलर, पोक्लेन, ड्रेसर, डेमग और हिटैची जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात विनिर्माताओं के उसके विकास के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की अनुमति दी जाए। आजकल विनिर्माण किए जा रहे मिट्टी हटाने के उपकरणों में 10 घन मीटर तक

क्षमता वाले शावेल्लस, 770 अश्व शक्ति तक के बुल्डोजर, 120 अश्व शक्ति तक के डम्पर, 8.5 घनमीटर क्षमता के एक्सावेटर, 280 अश्व शक्ति तक के स्क्रैपर तथा मोटर ग्रेडर्स तथा वार्किंग ड्रेगलाइन, सचल क्रेन आदि शामिल हैं। भवन निर्माण उपकरण विशेषकर सड़क निर्माण उपकरण जैसे ग्रेडर्स, लोडर्स, एक्स्केवेटर, वाइब्रेटर, कंपैक्टर, हॉटमिक्स प्लांट आदि का देश में ही निर्माण किया जा रहा है।

6.9.2 मिट्टी हटाने और निर्माण की मशीनरी का देश में उत्पादन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। आज कुल मिलाकर इन

मदों के संबंध में देश पूर्णतः आत्मनिर्भर है। अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण उद्योग में उपलब्ध कुल क्षमता लगभग 6000 नग हैं। भारत में अनेक मध्यम आकार की इकाइयों के अलावा संगठित क्षेत्र में 60 से अधिक उपकरण विनिर्माता हैं। बीईएमएल और केटर फिल्लर डम्पर और डोजर्स में जब कि एल एंड टी कोमात्सु और टेलीकॉम खुदाई उपकरणों में और एस्कार्टस जेसीबी बेकहो लोडर्स में अग्रणी हैं। सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास पर बल और प्राथमिकता दिए जाने से उद्योग के इस समूह के निकट भविष्य में विकसित होने की आशा है।

## प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

**7.1** किसी भी उद्यम के लिए बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने और बने रहने के लिए सतत जागरूक और तीव्र बल देते हुए अनुसंधान एवं विकास प्रयास करना एक अनिवार्य शर्त है। उद्योग क्षेत्र में विनियंत्रण लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हमारे दरवाजे पर पहुंच गई है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी का विश्व मानकों के अनुरूप उन्नयन करना आवश्यक हो गया है। प्रयोक्ता क्षेत्र की परिवर्तनशील मांग प्रौद्योगिकियों के चयन और उत्पादों की शुरूआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वास्तविकताओं को देखते हुए, भारतीय उद्योग जोकि पिछले चार दशक से सुरक्षा प्राप्त कर रहा था, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। अनुसंधान एवं विकास पर बल देने के महत्व को समझते हुए सरकार ने कुछ उत्प्रेरक कार्रवाई बिंदुओं पर विचार किया है। इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों ने भी तकनीकी और व्यावसायिक गठबंधनों तथा शुद्धतः अनुसंधान एवं विकास निविष्टियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन क्षेत्रों में देश को विशिष्ट लाभ प्राप्त हैं, वहां पर देश के लिए ब्रांड छवि विकसित करने के लिए उन क्षेत्रों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में विभाग द्वारा आरंभ किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:-

### 7.1.1 एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना

हाल में वातावरण में एसपीएम और ग्रीनहाऊस गैसों के वर्धित उत्पादन ने प्राधिकारियों तथा प्रशासकों को भी चिंतित कर दिया है। इसका परिणाम अनुसंधान और विकास संबंधी पहलों के माध्यम से उत्पादन की और अधिक सक्षम विधियों और ऊर्जा के उपयोग पर वर्धित बल हुआ। भारी उद्योग विभाग ने विद्युत मंत्रालय के समन्वय और 'भेल' तथा एनटीपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की

घनिष्ठ भागीदारी से एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना का समर्थन कर रहा है। आईजीसीसी संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र है जिसमें कोयले (अथवा तेल शोधनशाला अवशिष्ट जैसे कोई अन्य कार्बनिक ईंधन; यथा पैट कोक, विसब्रेकर तारकोल आदि) के गैसीकरण द्वारा गैस टर्बाइन के लिए ईंधन गैस उत्पादित की जाती है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया-जिसका निर्णय मुख्यतः उपलब्ध कोयले की किस्म और उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए गैस टर्बाइन के साथ उसके क्षमता एकीकरण द्वारा किया जाता है, का चयन आईजीसीसी संयंत्र की उच्चतर समग्र क्षमता प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

'भेल' ने अधिक राख की मात्रा वाले स्थानीय कोयले के लिए उपयुक्त एक प्रौद्योगिकी विकसित करने में पहले ही कुछ सफलता प्राप्त कर ली है और इस परियोजना के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की क्षमता सुधारने और प्रदूषण कम करने के अतिरिक्त "अधिक राख" वाले भारतीय कोयले का बेहतर उपयोग होगा।

### 7.1.2 आटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसरचना

भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और उसके परिणामस्वरूप माल और यात्रियों की आवाजाही की आवश्यकताओं के कारण हाल के वर्षों में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ-साथ उत्सर्जन और सुरक्षा संबंधी सांविधिक विनियमों के लागू होने से वाहनों का स्वतंत्र एवं व्यापक परीक्षण आवश्यक हो गया है तथा उनके प्रमुख कल-पुर्जों तथा छोटे कल-पुर्जों का देश में विनिर्माण और आयात किया जा रहा है। छोटी कारों के विनिर्माता के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के तौर पर स्थापित करने की घोषित नीति के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और

उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुरूपता लाने के लिए तथा आटो क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन के लिए परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना स्थापित करने को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

## 7.2 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

### 7.2.1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) -

#### अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

'भेल' द्वारा अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- 33 केवी, 16 केए रेटिंग तक के मध्यम वोल्टेज वेक्यूम सर्किट ब्रेकर में प्रयोग के लिए एक स्थायी चुम्बक आधारित एक्चुएटर (पीएमए) विकसित किया। पीएमए का इस समय प्रयुक्त स्प्रिंग प्रचालित एक्चुएटर कार्यतंत्र पर कुछ लाभ है जैसे साधारण डिजाइन, घटी हुई अनुरक्षण आवश्यकताएं, अधिक विश्वसनीयता, निम्न लागत आदि। पीएमए का प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया है और परिणाम प्रोत्साहनजनक हैं।
- ट्रांसफॉर्मर के आरएलए के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट ट्रांसफॉर्मर के वाइन्डिंग इंसुलेशन पेपर की संवेग वोल्टता सह्यता के परीक्षण के लिए एक नई विधि विकसित की। नवीन परीक्षण कार्य विधि के लिए पेटेंट दाखिल करने की संभाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है।
- 4X200 मेगावाट पर्वती एचईपी के लिए हेड अथवा 789 मी. के साथ छ: जेट पेल्टन हाइड्रोटेर्बाइन का मॉडल विकसित किया और उसका परीक्षण किया। परीक्षण के परिणाम इंगित करते हैं कि प्राप्त 92.271% की भारांशित औसत क्षमता बताई गई 92.225% की

क्षमता से बेहतर है। शीर्ष क्षमता 92.33% है। इस हेड रेंज के लिए पेल्टन टर्बाइन की यह क्षमता वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रतिस्पर्धी है।

- किसी पारेषण और वितरण नेटवर्क के केबल और ओपेन एयर टर्मिनलों के बीच परस्पर संपर्क के लिए शुष्क किस्म का 145 केवी एयर टू केबल टर्मिनेशन विकसित किया। ये जीआईएस आदि जैसे टर्मिनेटिंग उपस्कर के लिए भी उपयुक्त हैं। इस समय इनका आयात किया जा रहा है। दो प्रोटोटाइप निर्मित किए गए हैं और उनका आंतरिक रूप से परीक्षण किया गया है।
- डीएलडब्ल्यू द्वारा विनिर्मित किए जा रहे 4000 अश्वशक्ति डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में प्रयोग के लिए उपयुक्त 425 किवा तीन फेज वाला एसी प्रेरण मोटर विकसित किया। एक प्रोटोटाइप मोटर की डिजाइन बनाई गई है और उसका विनिर्माण किया गया है तथा सभी कार्यानिष्पादन परीक्षण सफलता पूर्वक पूरे किए गए।
- 6000 अश्वशक्ति इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में प्रयोग के लिए 850 कि.वा. तीन फेज वाले एसी प्रेरण मोटर की सुधरी हुई डिजाइन विकसित की। मोटर के लिए प्रौद्योगिकी मूल रूप से रेलवे के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इस प्रक्रिया पर एक पेटेंट दाखिल की जा रही है।
- थर्मल विद्युत संयंत्रों के आरएलए अध्ययन की यर्थाथता सुधारने के लिए एक नई तकनीक विकसित की।

वर्ष के दौरान 'भेल' द्वारा प्रारंभ की गई कुछ अन्य अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- 700 अश्वशक्ति डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए तीन फेज वाली एसी ड्राइव प्रणाली का विकास
- 150 केएचआई सिग्मा डिजाइन फीड पंप (बीएफपी)



विद्युत स्थानांतर क्षमता बढ़ाने और दो समानांतर 33 केवी पारेषण लाइनों के बीच प्रणाली स्थिरता सुधारने के लिए 2 एमवीए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर – फ्लैक्सबल एसी पारेषण (एफएसीटीएस) के क्षेत्र में एक अभिनव परिवर्तन

के लिए सुधरे हुए पम्प हाइड्रोलिक्स का विकास; 209 ई संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र का विनिर्माण और परीक्षण।

- माइक्रोकंट्रोलर आधारित मल्टी-फ्यूल फ्लेम स्केनर का विकास
- मल्टीपल बॉयलरों के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के नियंत्रण के लिए साझा टर्मिनल का विकास।
- अल्युमीनियम कंडक्टर का प्रयोग करते हुए कास्ट रेजिनड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर का विकास
- स्टेटिक टैप चेंजर के साथ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर का विकास
- एक्सआरपी 1103 बाऊल मिल की डिजाइन, विकास, विनिर्माण, उत्पादन और उस पर परीक्षण।
- लेजर वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए कृत्रिम आसचूना आधारित प्रौद्योगिकी का विकास
- एसआरएल 254 इंटेग्रेली गियर्ड टर्बो कंप्रेसर की डिजाइन और विकास

‘भेल’ में सूचना प्रौद्योगिकी सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है और इसे कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों यथा इंजीनियरी, विनिर्माण और सामग्री प्रबंध तथा उत्पादन कार्यों में उपयुक्त रूप से प्रयोग में लाया गया है।

कंपनी ने अपनी विनिर्माण इकाइयां, सेवा प्रभागों, परियोजना कार्यस्थलों और कार्यालयों को उपग्रह और स्थलीय दोनों नेटवर्क सेवाओं (वीसेट, आईएस डीएन, पट्टाधारित लाइनों

आदि) कर प्रयोग करते हुए जोड़कर अपनी नैगम स्तर व्यापक क्षेत्र नेटवर्क स्थापित किया है। इंजीनियरी कार्यों में कम्प्यूटर के प्रयोग पर मुख्य बल दिया गया है। सभी इंजीनियरी केंद्र डिजाइनिंग, मॉडलिंग, विश्लेषण और प्रारूपण आदि के लिए उन्नत इंजीनियरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए इंजीनियरी कार्य स्टेशनों से सुसज्जित हैं। ड्राइंग के प्रबंध के लिए अत्याधुनिक ड्राइंग आंकड़ा प्रबंध प्रणाली संस्थापित की जा रही है।

कंपनी नई अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के युग में ई-ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्वयं को तैयार कर चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी की मुख्य पहलों में उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) और वेब-आधारित अनुप्रयोग शामिल हैं। ‘भेल’ ई-मैप (कार्यनिष्पादन के माध्यम से अग्रसर होना) नामक सभी कार्यपालकों के लिए ई-संपर्क कार्यनिष्पादन प्रबंध प्रणाली कार्यान्वित करने वाला सरकारी क्षेत्र का पहला उद्यम बना।

### 7.2.2 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) - अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

कंपनी ने निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम प्रारंभ किया है:

- (क) जैवविक्षालन (बायोलीचिंग) के माध्यम से मैग्नेसाइट का शुद्धिकरण
- (ख) 1.5 टन क्षमता वाले निर्यात बैग की पुनःडिजाइन करने के माध्यम से भार वहन क्षमता में काफी सुधार लाया गया है। सेलम कारखाना पेलेटिंग के बिना सामग्री निर्यात करने में समर्थ है और इस प्रकार लागत की बचत हुई है।
- (ग) रेलवे बोर्ड की आवश्यकतानुसार रिवेट्स के स्थान पर हक बोल्ट का प्रयोग करना।

### 7.2.3 इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) - अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

कंपनी की पलक्कड इकाई ने बेलो सील्ड वाल्व का

विकास किया है, इसके लिए डीजीटीडी से आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त किया।

पूर्व में कोटा इकाई ने निम्नलिखित उत्पादों के आयात प्रतिस्थापन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है:

- नाभिकीय अनुप्रयोगों के लिए सोलेनॉयड वाल्व
- गले हुए धातु का तापक्रम मापने के लिए थ्रो-अवे थर्मोकपल्स
- मिनीएचर इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर्स

#### 7.2.4 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)- अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

कंपनी में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का मुख्य बल मौजूदा उत्पादों का निरंतर उन्नयन करने पर है ताकि वे घरेलू बाजार तथा साथ ही निर्यात बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। इसमें नए उत्पादों का विकास, उत्पाद विस्तार और प्रोटोटाइप विकास एवं वाणिज्यीकरण द्वारा आगे आने वाली उन्नत श्रृंखलाओं के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र को पुनः मान्यता दिलाना शामिल है। कंपनी की मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं:

##### उत्पादन विकास

- i) पेट्रो-रसायन और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 12 केवी 40 केए रेटिंग्स के वीसीबी पैनल का विकास।
- ii) 11 केवी 995 केवीए और 630 केवी के रेंज में ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मरों का विकास। ये ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर (तेल आधारित की बजाय) नए विनियमों के अनुसार उद्योगों द्वारा अपेक्षित हैं।
- iii) दूर-संचार क्षेत्र के लिए अपेक्षित सिंगल पोल डीसी कंटेक्टर्स के लिए उत्पाद अनुमोदन।
- iv) निर्यात बाजार के लिए 12 केवी रेंजिंग कास्ट करेंट ट्रांसफॉर्मर का विकास।

##### परीक्षण प्रमाण पत्रों का पुनः मान्यताकरण

- i) 33 केवी 25 के ए पोर्सलीन क्लेड आऊटडोर वीसीबी के लिए पूर्ण मान्यताकरण परीक्षण।
- ii) ट्रांस्विच/यूटीएस यूनिट का पुनः मान्यताकरण
- iii) 600ए तक एलटी कंटेक्टर्स के लिए किस्म परीक्षण
- iv) 3.3 केवी/6.6 केवी माइनिंग स्विचगियर के लिए अनिवार्य मान्यताकरण
- v) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास ढांचे को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

#### 7.2.5 ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड (बीएंडआर)-अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास

कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्य किए हैं:

- i) हाईवे और एक्सप्रेसवे
- ii) बेली ब्रिज
- iii) ग्रुप गेदरिंग स्टेशन
- iv) फर्नेस और हीटर
- v) वाइब्राफ्लॉट विधि द्वारा मृदा घनत्विकरण
- vi) रेलवे वैगन

ग्राहकों का प्रत्युत्तर प्रोत्साहनजनक रहा है।

#### 7.2.6 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) - अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप

कंपनी के अनुसंधान और विकास केंद्र ने जेलीपूरित केबलों के लिए नई और सस्ती मूलभूत कच्ची सामग्रियों के मानकीकरण पर अपना प्रयास जारी रखा है। इसने दूरसंचार केबल के लिए वाटर स्वेलेबल फ्लाइंग कंपाउंड और स्लीव विनिर्माण के लिए क्राँस लिंकड पॉलिथिन विकसित

किया है। यह टीईसी के सहयोग से विभिन्न ज्वाइंट क्लोजरों के परीक्षण और मानकीकरण का कार्य कर रही है।

### 7.3 नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

7.3.1 विगत में नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। वे हैं: द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी (सीईटी), सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीआईआई) और वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई)। और इनमें से केवल एफसीआरआई इस विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है जबकि शेष चार 'भेल' के नियंत्रणाधीन हैं।

#### 7.3.2 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) को प्रवाह नियंत्रण/परिशुद्धता के साथ मापन में संदर्भ/मानकीकरण का ढांचा विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जोकि द्रव प्रवाह के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक इंजीनियरी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है। यह सभी प्रकार के प्रवाह उत्पादों के लिए परीक्षण और अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसने अनेक संगठनों को संदर्भ/प्रमुख उपकरणों का राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंशांकन और आईएसओ-9000 पद्धति अपेक्षाओं में निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान कर आईएसओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता की है। भारत में पेट्रोलियम कंपनियों को परीक्षण कराने के लिए 20 बार एचपी तक वायु प्रवाह अंशांकन और परीक्षण सुविधा पहले ही स्थापित कर चुका है।

#### 7.3.3 सेरेमिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर

चीनी मिट्टी पर अनुसंधान के लिए सेरेमिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर की स्थापना का उद्देश्य भारतीय चीनी मिट्टी उद्योग को टेक्नोलॉजी के आधुनिकरण और परिष्कृत किस्म के उत्पादों के विकास में मदद देना है। उद्योग के लिए आवश्यक कई उत्पादों का विकास किया गया है और उनमें से कुछ का व्यावसायिक उपयोग किया जाने लगा है। 50 से अधिक संगठनों को परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।



एफसीआरआई में शोर अध्ययन की अद्वितीय सुविधा

#### 7.3.4 सेंटर फार इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, भोपाल

विद्युत परिवहन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1988 में मंजूरी दी गई। केन्द्र की क्षमताओं का विकास किया गया है और यहां बिजली से चलने वाले तमाम वाहनों के डिजाइन संबंधी सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण कर उनकी कार्यक्षमता, विश्वसनीयता तथा दक्षता में सुधार किया जाता है। केन्द्र में ऐसी सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें सभी परिस्थितियों में वाहनों की कार्यक्षमता का कम्प्यूटरों के जरिये और वास्तविक तौर पर परीक्षण संभव हो सकेगा।

#### 7.3.5 प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मुख्य



एजेंसी की भूमिका सौंप कर की है। संस्थान की परियोजना का उद्देश्य आर्थिक विकास के अवांछित दुष्परिणामों से बचने के लिए हवा, पानी आवास और ठोस अपशिष्ट से संबंधित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी का विकास करना है। संस्थान विभिन्न उद्योगों और ताप बिजली घरों को नियमित रूप से सेवाएं उपलब्ध कराता है।

### 7.3.6 वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुचिरापल्ली

वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान देश में अपनी तरह का पहला है। इसकी स्थापना भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के वित्तपोषण तथा तकनीकी सहायता से की गयी थी। संस्थान में अत्याधुनिक वेल्डिंग

अनुसंधान सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रान और लेजर बीम, फ्लेशबट, घर्षण और प्लाज्मा वैल्डिंग के अलावा परम्परागत आर्क वेल्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यहां फेटींग टैस्टिंग रेजीड्यूअल स्ट्रेम मेजरमेंट, रेजीड्यूअल लाइफ ऐसटीमेशन आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डब्ल्यूआरआई ने जर्मनी की जीटीजेड कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके अनुसार इस समय चल रहे परियोजना के दूसरे चरण में वेल्डिंग के संबंध में सहकारी अनुसंधान परियोजना शुरू की जाएगी। वर्ष 2003-2004 के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए डब्ल्यूआरआई द्वारा संगोष्ठियां संचालित की गई थीं।

## अल्पसंख्यकों का कल्याण

- 8.1 सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के संवर्धन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दायित्वों का निरीक्षण करना इस विभाग का प्रयास रहा है।
- 8.2 इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष है और निदेशक के स्तर के एक संपर्क अधिकारी को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है। यह कक्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आरक्षण रोस्ट्रों का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्यबल की मुख्य धारा में उनका एकीकरण यह सुनिश्चित करते हुए संवर्धित किया जाता है कि जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण कोई विभेद नहीं किया जाता।
- 8.3 हर वर्ष “कौमी एकता/सद्भावना दिवस” आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।
- 8.4 वर्ष 2003-2004 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने सेवा में अ.जा./ अ.ज.जा. के प्रतिनिधियों के संबंध में हिंदुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड के प्रबंधन के साथ संपर्क किया था। विभाग के प्रतिनिधियों ने भी समिति की सिफारिशों और अवलोकनों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उन बैठकों में भाग लिया।

## सतर्कता

- 9.1 विभाग के कर्मचारियों तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों को बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।
- 9.2 सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
  - सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
  - वित्तीय अनियमितता तथा कार्यविधिक, अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
  - बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।
- 9.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- 9.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।
- 9.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रस्तुति का अनुवीक्षण करता है।

## हिंदी का प्रगामी प्रयोग

- 10.1 विभाग के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए प्रयास वर्ष 2003-2004 के दौरान जारी रहे थे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठकों की और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का सुझाव दिया।
- 10.2 हिंदी सलाहकार समिति की भी दो बैठकें हुईं और उसने हिंदी के प्रयोग का संवर्धन करने के लिए विभाग को मूल्यवान दिशानिर्देश प्रदान किया।
- 10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने हैदराबाद, नोएडा (उत्तर प्रदेश) और मुम्बई स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यालयों और एचएमटी, बंगलौर तथा एचएमटी, औरंगाबाद की प्रोसेसिंग मशीनरी इकाई का निरीक्षण किया और जहां प्रगति से संतुष्टि व्यक्त की वहीं मूल्यवान दिशानिर्देश भी प्रदान किया। विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए कई उद्यमों का निरीक्षण किया, इस प्रकार भ्रमण किए गए इन उद्यमों को अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया।
- 10.4 सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों और परिपत्रों तथा संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए संसद प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्टें, सामान्य आदेश और कागजात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2003 से 30 सितम्बर, 2003 तक “हिंदी पखवाड़ा” आयोजित किया गया था, जिसके दौरान हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण, निबंध लेखन और पैराग्राफ लेखन सहित कई प्रतियोगिताएं संचालित की गईं। विभाग के अधिकारियों ने इन गतिविधियों में भाग लिया और गहरी दिलचस्पी दर्शाई। विजेता उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार दिए गए। हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण में प्रशिक्षण देने तथा साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तिमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा सही तरीके से भरने के लिए विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों की सभी संबंधित व्यक्तियों को जानकारी दी गई।
- 10.5 वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संवर्धन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे:
- राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीगण ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तदनुसार विभाग ने हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन नौगांव (असम) की एक इकाई और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड; विद्युत क्षेत्र (मुख्यालय), नोएडा को अभिज्ञात और अधिसूचित किया।
  - “आज का शब्द” के माध्यम से हिंदी सीखने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

10.6 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए

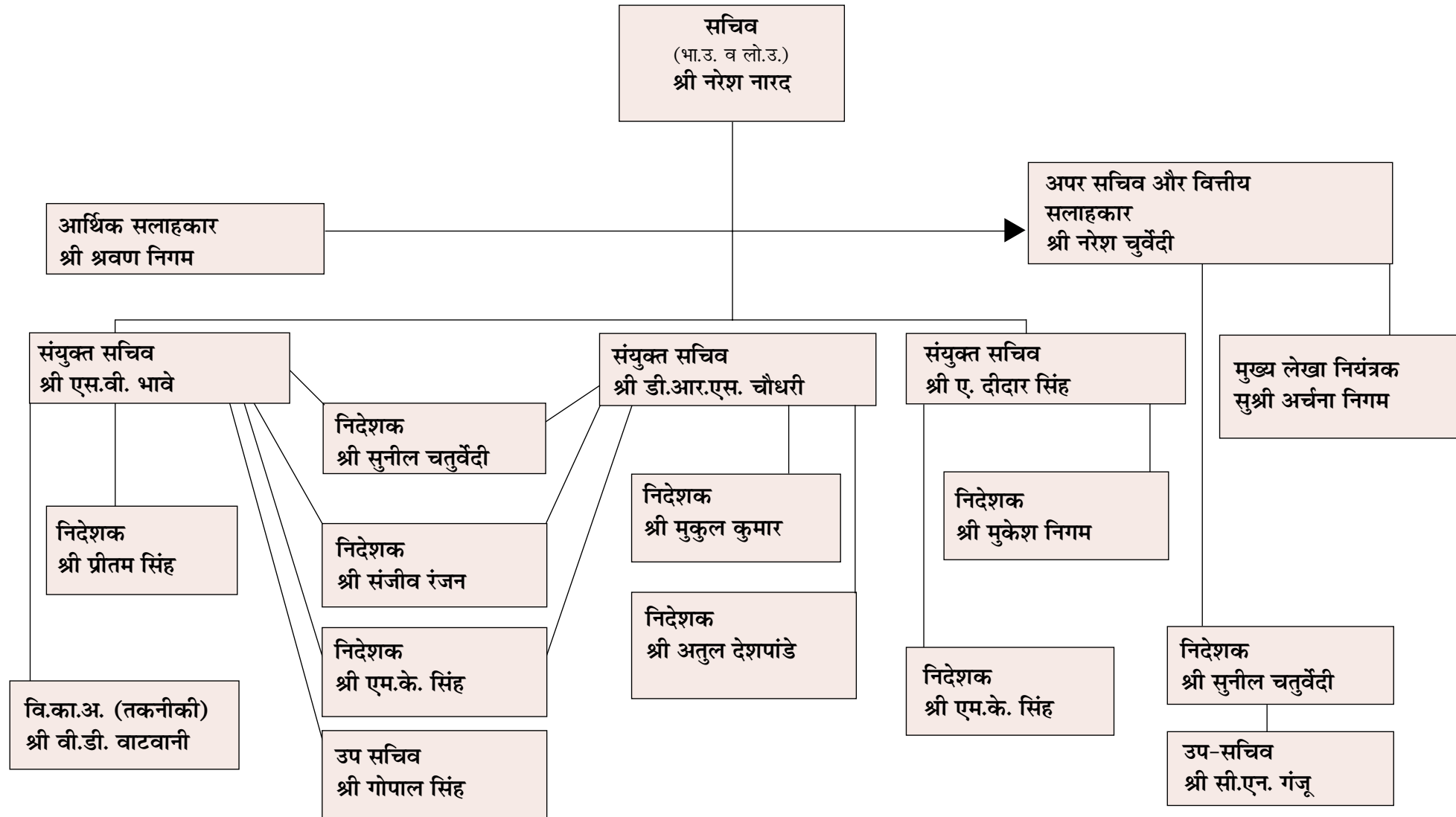
विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में “हिन्दी पखवाड़ा”/“हिन्दी दिवस” बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

## महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

- 11.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांत को महत्व देते हैं।
- 11.2 कामकाजी महिलाओं की लिंग समानता के अधिकार के आरक्षण और उसे लागू करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए इस विभाग में एक शिकायत समिति गठित की गई है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की जानकारी इस विभाग के कर्मचारियों को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 29 मई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों को विस्तृत दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए हैं।
- 11.3 विभाग का यह देखना सतत प्रयास है कि किसी भी कारण महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। महिलाओं को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण आदि जैसे विभाग के सभी कार्यक्रमों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभाग ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति गठित की है।

## भारी उद्योग विभाग का संगठन

दिनांक 31.03.04 की स्थिति के अनुसार



भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन  
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में  
सामान्य सूचना

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक (अंतिम)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए वाई एंड कं.), कोलकाता	1979	192.30
2	हुगली प्रिंटिंग, कोलकाता	1979	1.66
3	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल), नई दिल्ली	1956	3576.00
4	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) कोलकाता	1976	133.36
5	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1976	40.74
6	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), पटना	1978	16.71
7	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1987	7.15
8	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापट्टनम	1966	77.52
9	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद	1970	37.87
10	रिचर्डसन एंड कूडास (आर एंड सी), मुंबई	1972	30.71
11	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	20.14
12	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड हासपेट, कर्नाटक	1967	22.17
13	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता	1972	101.30
14	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	525.42



(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक (अंतिम)
15	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	309.88
16	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी) बंगलौर	1953	115.94
17	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बंगलौर	2000	212.14
18	एचएमटी वाचेज लि., बंगलौर	2000	187.62
19	एचएमटी चिनार वाचेज लि., बंगलौर	2000	10.46
20	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल) सिकन्दराबाद	1959	37.64
21	एचएमटी (बियरिंग्स)	1981	28.68
22	एचएमटी (इंटरनेशनल) बंगलौर	1974	22.00
23	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	1964	66.35
24	आरईआईएल, जयपुर	1981	8.02
25	नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल) कोलकाता	1957	9.17
26	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल), लखनऊ	1972	50.00
27	भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) दुर्गापुर	1972	5.91
28	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	643.29
29	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	1970	775.02
30	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), वेल्लोर, कोट्टायम	1983	348.58
31	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	1960	715.00

			(करोड़ रुपए में)
क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक (अंतिम)
32	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	1959	4.30
33	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) जयपुर	1964	6.70
34	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपालनगर	1949	115.00
35	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	1984	127.67
36	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	<b>16.37</b>
<b>कुल</b>			<b>8598.79</b>

- टिप्पणी: (i) 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।
- (ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) हैं और एक अप्रचालनात्मक सहायक कंपनी स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल, जीएमबीएच है।

31.3.2004 (अनन्तिम) की स्थिति के अनुसार अनु. जाति/अनु. जनजाति सहित भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजन की स्थिति

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				अनु. जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु. जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एण्ड्र्यू यूल् एंड कंपनी	227	117	15841	16185	257	654
2	हुगली प्रिंटिंग	8	8	49	65	1	-
3	भेल	9813	7219	26927	43959	8095	1738
4	बीएससीएल	124	164	1348	1636	-	-
5	ब्रेथवेट	77	47	448	572	-	-
6	बीडब्ल्यूईएल	45	44	900	989	88	2
7	बीबीजे	41	10	42	93	6	1
8	बीएचपीवी	393	181	1150	1724	301	118
9	बीपीसीएल	227	51	979	1257	204	2
10	आर एंड सी	63	12	36	111	6	-
11	टीएसएल	84	63	271	418	54	-
12	टीएसपी	55	34	329	418	86	9
13	बीएंडआर	458	532	411	1401	169	5
14	एचसीएल	467	474	2271	3212	849	235
15	एचईसी	643	607	2487	3737	310	667
16	एचएमटी	297	176	2095	2568	559	108
17	एचएमटी (एमटी)	1035	540	3139	4714	822	217
18	एचएमटी (वाचेज)	206	241	1779	2226	395	99
19	एचएमटी (चिनार वाच)	22	108	530	660	53	4
20	प्रागा टूल्स लिमिटेड	94	6	459	559	98	13
21	एचएमटी (बी)	56	55	272	383	46	-
22	एचएमटी (आई)	43	27	11	81	12	3

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				अनु. जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनु. जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	आईएल	242	735	820	1797	294	83
24	आरईआईएल	49	42	99	190	27	11
25	एनआईएल*	4	67	211	282	49	9
26	एसआईएल	239	81	1491	1811	307	2
27	बीओजीएल	12	2	189	203	21	4
28	सीसीआई	188	206	1213	1607	198	129
29	एचपीसी	604	217	2137	2958	275	234
30	एचएनएल	191	85	849	1125	78	4
31	एचपीएफ	95	70	929	1094	179	56
32	एचएसएल	12	29	103	144	22	7
33	एसएसएल	7	28	108	143	39	10
34	नेपा	129	0	1354	1483	108	23
35	टीसीआईएल	35	44	275	354	17	3
36	ईपीआईएल	361	91	17	469	77	13
<b>जोड़</b>		<b>16646</b>	<b>12413</b>	<b>71569</b>	<b>100628</b>	<b>14102</b>	<b>4463</b>

- टिप्पणी: (i) 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।
- (ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उपक्रमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएल और बीवाईएल) हैं और एक अप्रचालनात्मक सहायक कंपनी स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।
- \*दिनांक 31.3.2003 की स्थितिनुसार।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र  
के उपक्रमों के उत्पादन कार्यनिष्पादन को  
दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (अंतिम)	2004-2005 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	167.02	112.45	106.54	97.96	163.87
2	हुगली प्रिंटिंग	3.32	7.11	11.64	9.25	10.00
3	भेल	6348.00	7287.00	7482.00	8653.00	9200.00
4	बीएससीएल	235.02	118.79	208.35	176.92	276.36
5	ब्रेथवेट	147.11	75.20	75.15	65.44	102.37
6	बीडब्ल्यूईएल	113.44	74.54	39.05	11.91	96.76
7	बीबीजे	37.51	36.47	41.93	29.80	40.00
8	बीएचपीवी	264.27	223.17	220.13	41.05	150.00
9	बीपीसीएल	59.51	66.42	68.00	47.26	60.00
10	आर एंड सी	74.90	53.69	47.47	24.81	25.00
11	टीएसएल	13.70	24.58	30.22	0.49	5.00
12	टीएसपी	37.42	15.03	10.84	7.47	15.00
13	बी एंड आर	334.49	344.21	364.24	403.75	450.00
14	एचसीएल	875.08	579.08	403.46	104.86	491.91
15	एचईसी	147.19	162.10	141.82	149.39	231.00
16	एचएमटी	296.57	217.68	141.45	129.35	283.85
17	एचएमटी (एमटी)	200.95	227.76	197.07	178.34	310.00
18	एचएमटी (वाच)	144.08	79.06	44.49	25.65	200.00
19	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.78	2.11	2.72	1.98	10.00
20	प्रागा टूल्स लि.	6.42	3.98	6.29	8.12	22.58
21	एचएमटी (बी)	45.00	41.68	18.40	23.60	60.00
22	एचएमटी (आई)	46.81	58.69	43.92	29.58	61.20

		(करोड़ रुपए में)				
क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (अनंतिम)	2004-2005 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
23	आईएल	106.74	107.85	131.53	139.02	165.00
24	आरईआईएल	32.03	35.45	44.00	44.05	55.65
25	एनआईएल	5.63	5.48	5.14	3.62	4.25
26	एसआईएल	116.79	124.65	134.50	157.15	168.62
27	बीओजीएल	3.71	3.09	2.02	0.05	2.41
28	सीसीआई	74.85	131.45	122.00	132.16	199.18
29	एचपीसी	468.83	521.73	564.27	569.81	582.93
30	एचएनएल	254.02	242.24	204.05	250.94	246.75
31	एचपीएफ	31.97	42.40	30.32	28.43	29.00
32	एचएसएल	3.80	4.19	5.00	6.96	9.04
33	एसएसएल	3.83	6.09	6.22	6.20	9.25
34	नेपा	131.75	99.97	32.04	38.15	115.16
35	टीसीआईएल	94.57	61.36	128.22	144.88	150.65
36	ईपीआई	260.97	390.53	358.71	400.78	508.72
<b>कुल</b>		<b>11189.08</b>	<b>11587.28</b>	<b>11473.20</b>	<b>12142.18</b>	<b>14507.31</b>

- टिप्पणी: (i) 9 सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।
- (ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उपक्रमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएल और बीवाईएल) और एक अप्रचालनात्मक सहायक कंपनी स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र  
के उद्यमों का (कर-पूर्व) लाभ(+)/हानि (-)  
दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (अंतिम)	2004-2005 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
<b>(क) लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम</b>						
1	हुगली प्रिंटिंग	0.05	0.41	1.72	1.02	1.23
2	भेल	294.00	663.00	803.00	979.00	920.00
3	एचपीसी	32.80	63.75	40.60	42.15	43.59
4	एचएनएल	30.35	6.45	-7.55	9.00	5.93
5	बी एंड आर	3.39	3.61	3.85	3.07	6.00
6	ईपीआई	17.76	9.44	3.01	2.26	5.00
7	एचएमटी (आई)	0.38	0.54	0.34	0.11	0.70
8	आरईआईएल	0.43	0.60	3.55	3.58	4.35
9	एसआईएल	5.10	2.26	2.65	2.80	2.75
<b>उप-योग (क) लाभ कमा रही कंपनियां</b>		<b>384.26</b>	<b>750.06</b>	<b>851.17</b>	<b>1042.99</b>	<b>989.55</b>

<b>(ख) हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम</b>						
10	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी	-26.78	-39.45	-60.66	-55.04	-6.89
11	ब्रेथवेट	1.74	-33.55	-21.89	-23.42	-15.78
12	बीएससीएल	-45.22	-78.35	-73.74	-77.95	-77.92
13	बीबीजे	0.60	0.57	-4.39	-5.88	-2.64
14	बीडब्ल्यूईएल	-4.69	-26.87	-8.99	-22.15	-9.93
15	टीएसपी	0.07	-0.66	-2.63	-99.98	-14.50
16	बीएचपीवी	0.94	1.72	1.53	-158.81	-20.00
17	बीपीसीएल	-5.59	-11.86	-8.51	-24.75	-8.20
18	आर एंड सी	-8.15	-19.21	-28.19	-40.64	-27.00
19	टीएसल	-45.92	-12.23	-8.54	-27.00	-13.00

(करोड़ रुपए में)						
क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (अनंतिम)	2004-2005 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
20	एचसीएल	-71.41	-236.08	-256.31	-302.16	-298.30
21	एचईसी	-189.26	-173.78	-173.82	-136.12	-32.33
22	एचएमटी (धारक कंपनी)	24.41	10.24	-34.41	-6.64	10.75
23	एचएमटी (बी)	2.21	1.02	-15.03	-9.81	8.65
24	एचएमटी (एमटी)	-96.17	-70.65	-102.05	-113.96	-48.84
25	एचएमटी (वाच)	-59.00	-106.00	-113.00	-115.41	-11.00
26	एचएमटी (चिनार)	-7.95	-10.16	-6.31	-22.18	5.90
27	पीटीएल	-34.42	-35.06	-37.50	-10.79	-1.66
28	आईएलके	-34.52	-30.49	-29.18	-28.63	-1.23
29	एनआईएल	-4.48	-5.90	-2.08	-2.15	-2.29
30	बीओजीएल	-24.88	-31.87	-35.11	-39.95	-40.82
31	सीसीआई	-230.76	-215.33	-215.36	-61.70	-209.06
32	एचपीएफ	-328.16	-353.72	-385.39	-457.13	-518.50
33	एचएसएल	-2.19	-1.91	-2.78	-2.26	-1.15
34	एसएसएल	-3.27	-3.02	-2.66	-2.89	-2.11
35	नेपा	4.86	-35.16	-50.90	-41.18	-31.81
36	टीसीआईएल	-66.43	-67.41	-16.91	-37.02	-67.32
<b>उप-योग (ख) हानि उठा रही कम्पनियां</b>		<b>-1254.42</b>	<b>-1585.17</b>	<b>-1694.81</b>	<b>-1925.6</b>	<b>-1436.98</b>
<b>कुल-योग (क+ख)</b>		<b>-870.16</b>	<b>-835.11</b>	<b>-843.64</b>	<b>-882.61</b>	<b>-447.43</b>

- टिप्पणी: (i) 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।
- (ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उपक्रमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएल और बीवाईएल) और एक अप्रचालनात्मक सहायक कंपनी इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।
- (iii) लाभ कमा रहे एवं हानि में चल रहे सरकारी उपक्रमों का वर्गीकरण वर्ष 2003-04 (अनंतिम) परिणामों पर आधारित है।



## भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्न ओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक ऊपरी खर्चों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशत					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक ऊपरी खर्च का प्रतिशत				
		2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (वास्तविक)	2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (अनतिम)	2004-2005 (लक्ष्य)	2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (वास्तविक)	2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (अनतिम)	2004-2005 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एण्ड्र्यू यूल एंड कं.	34.13	47.58	54.85	58.23	26.00	4.92	6.60	5.92	5.60	5.30
2	हुगली प्रिंटिंग	30.87	21.78	13.48	17.08	16.85	2.74	1.31	1.02	1.03	1.15
3	भेल	26.09	19.83	20.11	19.24	19.06	3.28	3.14	2.52	2.85	2.72
4	बीएससीएल	39.94	42.77	20.54	16.29	15.49	2.89	4.68	2.08	2.77	2.22
5	ब्रेथवेट	23.97	52.64	29.59	16.18	12.72	1.30	2.78	1.51	1.83	1.58
6	बीडब्ल्यूईएल	34.18	65.53	60.34	158.72	18.84	1.54	0.95	1.08	3.38	0.61
7	बीबीजे	14.40	12.11	12.00	15.34	12.50	0.91	0.90	0.77	1.30	0.88
8	बीएचपीवी	20.25	21.17	29.18	52.80	16.21	2.54	2.79	2.17	4.04	2.46
9	बीपीसीएल	49.44	32.68	42.27	50.07	27.58	5.38	3.78	4.42	5.60	4.50
10	आर एंड सी	8.31	11.43	27.75	19.61	3.40	1.07	1.13	0.94	1.37	0.20
11	टीएसएल	97.73	41.42	219.68	630.92	65.20	18.25	7.00	3.71	17.20	16.80
12	टीएसपी	25.35	21.47	69.60	86.29	31.93	1.40	1.56	3.91	4.10	2.40
13	बी एंड आर	10.61	10.64	11.49	10.02	7.54	0.84	0.78	0.81	0.69	0.57
14	एचसीएल	5.96	10.33	15.28	59.96	12.28	1.11	1.18	1.62	5.31	1.33
15	एचईसी	67.45	46.21	34.58	32.43	24.43	13.14	7.30	4.82	6.38	2.84
16	एचएमटी (धारक)	23.04	21.13	32.43	38.60	17.84	2.56	2.58	3.48	3.95	1.82
17	एचएमटी (एमटी)	59.00	39.00	43.00	57.00	30.00	8.00	4.00	3.00	4.00	3.00
18	एचमटी (वाचेज)	58.73	67.74	105.55	153.66	16.00	5.82	6.29	9.06	18.18	1.88
19	एचएमटी चिनार	499.00	511.00	1074.00	648.00	122.00	47.00	69.00	152.00	97.00	17.00
20	प्रगा टूल्स	142.00	209.00	109.00	78.00	25.00	41.00	56.00	42.00	30.00	10.00
21	एचएमटी (बी)	27.00	30.00	54.00	31.52	18.00	4.00	4.00	5.00	5.59	2.00
22	एचएमटी (आई)	5.15	3.23	4.66	7.03	3.25	1.07	0.70	0.98	1.35	0.75
23	आईएल	39.38	36.87	28.90	24.14	18.79	2.20	2.05	1.70	1.38	1.15
24	आरआईआईएल	13.40	11.23	9.82	7.45	8.67	2.62	2.54	2.59	1.63	1.87
25	एनआईएल	62.00	64.00	48.17	18.38	17.21	0.18	0.16	0.16	0.08	0.23
26	एसआईएल	18.84	18.65	16.70	18.16	16.28	4.44	4.63	4.74	4.78	4.34
27	बीओजीएल	107.39	83.82	202.31	325.98	87.18	31.03	23.24	56.58	38.80	10.38
28	सीसीआई	68.23	42.54	32.07	22.85	12.06	27.86	12.64	11.61	3.43	3.01
29	एचपीसी	9.71	10.14	9.47	9.68	12.78	5.30	4.99	4.45	4.58	4.09
30	एचएनएल	8.51	9.74	8.71	8.89	11.76	5.17	5.47	4.75	3.66	3.20
31	एचपीएफ	91.15	70.74	49.07	46.86		3.76	2.39	2.74	2.55	
32	एचएसएल	69.07	64.73	63.44	33.00	31.14	6.06	4.77	3.67	3.10	3.40
33	एसएसएल	90.58	43.04	47.26	40.00	39.12	6.93	3.19	3.22	2.70	2.76
34	नेपा	12.00	20.00	30.00	43.00	13.00	2.00	3.00	5.00	2.00	2.00
35	टीसीआईएल	34.28	31.70	14.77	18.34	10.15	5.65	4.26	5.10	4.14	4.17
36	ईपीआईएल	6.85	4.41	5.27	4.37	3.59	1.01	0.91	1.00	0.94	0.72

टिप्पणी: (i) 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उपक्रमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएल और बीवाईएल) है और एक अप्रचालनात्मक सहायक कंपनी स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।

## भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की क्रयादेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	दिनांक 1.10.1999 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2003 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	117.35	130.78	140.05	131.66	103.54
2	हुगली प्रिंटिंग	0.25	0.20	0.11	2.84	1.10
3	भेल	10082.00	10526.00	10029.00	12573.00	19000.00
4	बीएससीएल	112.50	123.20	86.83	111.02	174.74
5	ब्रेथवेट	155.23	156.20	19.98	106.85	130.59
6	बीडब्ल्यूईएल	77.79	108.56	33.24	32.68	115.48
7	बीबीजे	30.19	57.79	40.09	51.99	45.24
8	बीएचपीवी	158.52	309.20	183.05	130.41	115.50
9	बीपीसीएल	26.24	66.10	73.91	38.83	43.50
10	आर एंड सी	83.21	96.80	79.71	158.15	69.20
11	टीएसएल	50.85	46.70	38.58	37.72	36.00
12	टीएसपी	26.43	55.00	25.95	32.65	24.40
13	बी एंड आर	239.73	325.40	375.77	385.16	636.40
14	एचसीएल	72.16	185.49	243.49	351.63	164.00
15	एचईसी	169.03	150.93	150.32	99.63	192.90
16	एचएमटी (धारक)	NA	NA	NA	NA	NA
17	एचएमटी (एमटी)	140.57	133.00	145.08	99.19	111.23
18	एचएमटी (वाचेज़)	NA	NA	NA	NA	NA
19	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	NA	NA	NA	NA	NA
20	प्रागा टूल्स	12.34	12.74	8.12	5.30	4.47
21	एचएमटी (बी)	18.02	2.25	2.28	4.37	2.15
22	एचएमटी (आई)	28.19	38.30	42.53	53.15	12.11
23	आईएल	64.00	36.03	34.85	53.82	88.50
24	आरआईआईएल	4.91	6.04	19.43	16.94	27.09
25	एनआईएल	4.14	2.16	2.51	2.13	0.38
26	एसआईएल	-	-	-	-	-
27	बीओजीएल	0.59	0.41	0.44	0.52	0.59
28	सीसीआई	22.30	12.29	110.41	4.17	-
29	एचपीसी	9.37	24.89	24.10	4.15	15.21
30	एचएनएल	-	-	-	-	-
31	एचपीएफ	-	-	0.00	5.10	2.60
32	एचएसएल	1.00	2.21	0.39	3.22	6.12
33	एसएसएल	2.05	1.20	2.10	1.03	2.07
34	नेपा	16.25	27.80	6.59	5.94	4.99
35	टीसीआईएल	15.84	9.00	5.00	4.80	5.39
36	ईपीआईएल	261.00	430.00	626.45	595.78	891.26
<b>कुल</b>		<b>12002.05</b>	<b>13076.67</b>	<b>12550.36</b>	<b>15103.83</b>	<b>21923.84</b>

- टिप्पणी: (i) 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।
- (ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उपक्रमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएल और बीवाईएल) और एक अप्रचलनरत सहायक कंपनी स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।

## भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात-निष्पादन

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	1999-2000			2000-2001			2001-2002			2002-2003			2003-2004 (अनन्तिम)		
		वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल	वास्तविक	मानित	कुल
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं. लि.	10.49	17.79	28.28	8.86	12.00	20.86	8.09	0.00	8.09	6.51	2.10	8.61	0.33	3.40	3.73
2	भेल	355.00	1395.00	1750.00	247.00	1426.00	1673.00	987.00	1524.00	2511.00	637.00	1529.00	2166.00	603.00	1484.00	2087.00
3	बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि.	2.69	0.17	2.86	2.80	0.00	2.80	4.89	0.00	4.89	1.48	13.17	14.65	2.48	4.90	7.38
4	ब्रेथवेट एवं कं. लि.	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भारत बैंगन इंजी. कं. लि.	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीबीजे	0.00	2.05	2.05	0.00	2.26	2.26	0.00	1.43	1.43	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00
7	भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लि.	12.78	5.19	17.97	2.00	2.92	4.92	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	भारत पम्पस एंड कं. लि.	0.00	0.14	0.14	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	0.00	5.27	5.27
9	रिचर्डस एंड कूडास (1972) लि.	0.41	3.06	3.47	0.34	0.99	1.33	0.24	0.30	0.54	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
10	त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्स लि.	2.58	7.03	9.61	2.58	7.03	9.61	1.69	1.86	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	8.47	0.00	8.47	8.97	0.00	8.97	0.69	0.00	0.69
13	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हैवी इंजीनियरिंग कं. लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	एचएमटी (एचमटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	एचएमटी (वाच)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	प्रागा टूल्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.08	0.77	0.85
18	एचएमटी (बियरिंग्स) लि.	0.05	0.00	0.05	0.11	0.00	0.11	0.15	0.00	0.15	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
19	एचएमटी (आई) लि.	34.37	0.00	34.37	39.18	0.00	39.18	49.68	0.00	49.68	34.73	0.00	34.73	29.58	0.00	29.58
20	इंस्ट्रुमेंटेशन लि.	0.10	1.40	1.50	0.80	0.00	0.80	0.25	1.34	1.59	0.51	1.89	2.40	0.26	3.85	4.11
21	आरईआई लि.	0.42	0.00	0.42	0.25	0.00	0.25	0.08	0.00	0.08	0.09	0.00	0.09	0.16	0.15	0.31
22	एनआईएल	0.01	0.00	0.01	0.09	0.00	0.09	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0	0.00	0.00
23	स्कूटर्स इंडिया लि.	6.26	0.00	6.26	1.29	0.00	1.29	0.31	0.00	0.31	0.94	0.00	0.94	1.05	0.00	1.05
24	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	26.90	3.21	30.11	3.39	14.58	17.97	0.00	25.17	25.17	0.00	10.32	10.32	0.00	3.12	3.12
25	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. कं.	0.01	0.00	0.01	0.36	0.00	0.36	0.40	0.00	0.40	0.59	0.00	0.59	0.31	0.00	0.31
26	हिन्दुस्तान साल्ट लि.	0.73	0.00	0.73	0.81	0.00	0.81	0.92	0.00	0.92	0.65	0.00	0.65	0.38	0.00	0.38
27	सांभर साल्टस लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
28	इंजीनियरिंग प्रो. (इंडिया) लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>		<b>452.80</b>	<b>1435.24</b>	<b>1888.04</b>	<b>318.58</b>	<b>1465.79</b>	<b>1784.37</b>	<b>1062.29</b>	<b>1560.47</b>	<b>2622.76</b>	<b>692.36</b>	<b>1561.90</b>	<b>2254.26</b>	<b>638.42</b>	<b>1505.46</b>	<b>2143.88</b>

31.3.2004 (अनंतिम) के अनुसार भारी उद्योग विभाग  
के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी,  
निवल परिसंपत्ति और संचयी लाभ (+)/हानि (-)

(करोड़ रुपए में)

क्र. संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/हानि (-)
		सरकारी/सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	एण्ड्र्यू यूल एंड कं.*	54.34	3.93	-72.95	-137.01
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03		2.05	0.52
3	भेल*	165.76	79.00	4708.00	4559.00
4	बीएससीएल	128.26		-444.21	-572.47
5	ब्रेथवेट	106.37		-105.06	-203.43
6	बीडब्ल्यूईएल	10.10		-78.09	-73.90
7	बीबीजे	2.14		-10.17	-12.31
8	बीएचपीवी	73.57		-419.27	-350.45
9	बीपीसीएल	53.53		-113.54	-157.93
10	आर एंड सी	54.84		-111.91	-146.60
11	टीएसएल	21.02		-211.01	-232.02
12	टीएसपी	21.74		-95.81	-103.58
13	बी एंड आर	13.98		43.64	30.89
14	एचसीएल	415.19	1.67	-954.71	-1428.31
15	एचईसी	448.12		-1328.30	-1824.39
16	एचएमटी	462.17	8.50	12.43	-409.97
17	एचएमटी (मशीन टूल्स)	10.70		-560.33	-382.83
18	एचएमटी (वाच)	5.49		-516.30	-393.8
19	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	1.41		-85.95	-79.13
20	प्रागा टूल्स	17.06	19.11	-252.31	-288.48
21	एचएमटी (बी)	8.99	0.24	-21.57	-15.68
22	एचएमटी (आई)	0.48		21.19	20.00
23	आईएल	79.64		-178.29	-227.61
24	आरआईआईएल	0.64	0.61	7.90	6.65
25	एनआईआईएल*	8.31		-232.18	-240.48
26	एसआईएल	42.99		53.65	10.81
27	बीओजीएल	7.14		-363.13	-370.03
28	सीसीआई	429.28		-1485.39	-1914.67
29	एचपीसी	700.38		622.18	-78.20
30	एचएनएल	82.54		192.96	114.96
31	एचपीएफ	180.68	19.19	-2442.52	-2661.36
32	एचएसएल	9.11		-10.03	-19.14
33	एसएसएल	1.00	0.00	-13.95	-14.95
34	नेपा	103.00	2.39	-158.43	-246.62
35	टीसीआईएल	93.10		-585.80	-678.80
36	ईपीआईएल*	35.42		113.59	32.46
<b>जोड़</b>		<b>3849.52</b>	<b>134.64</b>	<b>-5073.62</b>	<b>-8488.86</b>

टिप्पणी: (i) 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और 3 सरकारी क्षेत्र के उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी और एनपीपीसी) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 36 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) और एक अप्रचलनरत सहायक कंपनी स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।

\*दिनांक 31.3.2003 की स्थितिनुसार।

## नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त अपनी रिपोर्ट में भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियां/अवलोकन किए गए हैं:

आदेश देने के पूर्व अपनी वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अगस्त, 1996 में एक डीजी सेट प्राप्त किया, जो 16.71 करोड़ रुपए के व्यय से बचने के लिए उपयुक्त रहा।

### (2003 की रिपोर्ट 3 का पैरा 13.1.1) वाणिज्यिक

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने रेलवे को लोकोमोटिव की आपूर्ति की और उन्हें उसे वारंटी अवधि के दौरान कार्य दशा में रखने की अपेक्षा थी। चूंकि 'भेल' अपने वारंटी दायित्व को पूरा करने में विफल रहा इसलिए यह वर्ष 1997-1998 से 2001-2002 तक के दौरान 6.82 करोड़ रुपए का पट्टा किराया वसूल नहीं कर सका।

### (2003 की रिपोर्ट 3 का पैरा 13.2.1) वाणिज्यिक

## संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एवाई एंड कं.	एण्ड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आर्थोल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
ब्रेथवेट	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीएससीएल	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
सी डॉट	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोलड
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियम इकानामिक कम्युनिटी
ईओटी	इलैक्ट्रीकली आपरेटेड ट्रांली
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबशन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
आईएलके	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन

जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन आटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनसीएमपी	नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
एनआईडीसी	नेशनल इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसई	पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैण्डर्ड्स आर्गनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
एसएचए	शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसपीए	शेयर परचेज एग्रीमेंट
एसएसएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफको	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड

